महानगर नई दिल्ली शनिवार 11 अप्रैल, 2020, रु. 5.00 (10 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

आज देशबंदी बढ़ाने के आसार के बीच

पंजाब ने एक मई तक बढ़ाई पूर्णबंदी

चंडीगढ़, 10 अप्रैल (जनसत्ता)।

कोरोना महामारी के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति तक पहुंचने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पूर्णबंदी व कर्फ्यू एक मई तक बढ़ा दिया। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार ने महामारी के सामुदायिक प्रसार को रोकने और गेहूं की कटाई/खरीद के सीजन के चलते मंडियों में भीड़भाड़ रोकने के उद्देश्य से यह फैसला किया।

संकट से पार पाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला

अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनेगी

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार होने वाली मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अवगत करवाएंगे।

आगामी हफ्तों में महामारी फैलने के गंभीर अंदेशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी व कर्फ्यू बाकी पेज 8 पर

पूर्णबंदी बढ़ाने पर प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देशव्यापी पूर्णबंदी को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस संवाद में फैसला लिया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिनों के देशव्यापी पूर्णबंदी को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

17 दिन

नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूर्ण बंदी की अवधि बढ़ाने का बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्रालय ने राज्यों से मांगे सुझाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

गृह मंत्रालय ने देश में पूर्णबंदी को लेकर राज्य सरकारों के सुझाव मांगे हैं। राज्यों से पूछा गया है कि क्या ज्यादा श्रेणियों में लोगों और सेवाओं को बंद से छूट दी जा सकती है। संकेत हैं कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूर्णबंदी को दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है।

धार्मिक जलसों और जुलूसों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश

अफवाहें रोकने के लिए सोशल मीडिया पर रखी जाएगी निगरानी

इस पत्र में गृह मंत्रालय ने उन कदमों की जानकारी दी है, जिन्हें पूर्ण बंदी के दौर में कड़ाई से लागू कराया जाना है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने कहा कि आगामी त्योहारों- उत्सवों को देखते हुए पूर्ण बंदी का कड़ाई से अनुपालन करवाएं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक जलसे एवं जुलूस की अनुमति नहीं दें। गुरुवार को शब-ए-बारात थी, आज गुड फ्राइडे है। बैसाखी, रंगोली बिहू, विशु, पोइला बैसाख, बाकी पेज 8 पर

राजकाज

कुनैन कथा

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

कोरोना मृतकों की संख्या 96 हजार के पार

ब्रूसेल्स, 10 अप्रैल (एएफपी)।

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी हर दिन नए आंकड़ों के साथ दहशत लेकर आ रही है और गुरुवार तक दुनिया भर में इस घातक विषाणु के कारण मृतकों का आंकड़ा 96,000 के पार चला गया। हालांकि अमेरिका और यूरोप में इस संकट के चरम पर पहुंचने के बाद अब इसकी दहशत कम होने की उम्मीद के कुछ अस्थायी संकेत दिखाई देने शुरू हुए हैं।

अमेरिका में गुरुवार को 1700 लोगों की मौत

यूरोपीय समुदाय में 550 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर बनी सहमति

आर्थिक आपदा की तस्वीर भी साफ होने लगी है जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महा आर्थिक मंदी के प्रति आगाह किया है। आंकड़े बताते हैं कि 1.7 करोड़ अमेरिकियों की नौकरी चली गई है जबकि यूरोपीय संघ का आर्थिक राहत पैकेज समझौता बुरी खबरों के बीच कुछ राहत लेकर आया है।

अमेरिका में गुरुवार को 1,700 और लोगों की मौत हुई जबकि यूरोप में सैकड़ों और लोगों की मौत हुई जिसके बाद बाकी पेज 8 पर

नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ की साजिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

नेपाल की सीमा के रास्ते एक कुख्यात हथियार और जाली मुद्रा तस्कर द्वारा कोरोना विषाणु संक्रमितों को भारत में भेजने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) ने अपनी सभी टुकड़ियों को सतर्क कर दिया है। एसएसबी ने अपने नेपाली समकक्ष सशस्त्र पुलिस बल को भी इसकी सूचना दे दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क किया है।

> “खुफिया जानकारी सामने आई है कि विभिन्न देशों में काम करने वाले लगभग दो सौ भारतीय पांच-छह पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सीमा के उस पार चंदनबरसा और खैरवा गांव में मस्जिद में ठहरे हुए हैं।
> -एसएसबी के महानिदेशक

एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र के मुताबिक, भारत और नेपाल- दोनों देश सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से कदम उठा रहे हैं। सामने आई खुफिया जानकारी में कहा गया है कि विभिन्न देशों में काम करने वाले लगभग 200 भारतीय पांच-छह पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सीमा के उस पार चंदनबरसा और खैरवा गांव में मस्जिद में ठहरे हुए हैं।

इससे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा में स्थित एसएसबी की 47वीं बटालियन को स्थानीय जिला प्रशासन ने पत्र के जरिए इस आशय की जानकारी दी थी कि सीमा पार से कोरोना संक्रमित संदिग्धों को भारत में दाखिल कराया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संदिग्धों को भारत में दाखिल कराया गया है। इन लोगों का मकसद भारत में कोरोना संक्रमण फैलाना है।

पत्र के मुताबिक भारत में दाखिल होने वाले लोगों को जालिम बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में नबी करीम, चांदनी महल और जाकिर नगर सील

'ऑपरेशन शील्ड' के तहत सील किए गए इलाकों की संख्या 30 हो गई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

कोरोना विषाणु संक्रमण के खतरे के बीच दिल्ली के तीन नए इलाकों को सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में पुरानी दिल्ली का नबी करीम व चांदनी महल और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली का जाकिर नगर इलाका शामिल है। मध्य जिले की डीएम निधि श्रीवास्तव व दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली की डीएम हरलीन कौर ने यह जानकारी दी।

एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना का कहर थामने के लिए 'ऑपरेशन शील्ड' को बड़े पैमाने पर चलाने का निर्णय लिया

एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना का कहर थामने के लिए 'ऑपरेशन शील्ड' को बड़े पैमाने पर चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 30 इलाकों को सील किया गया। सील किए गए सभी इलाकों में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सभी जरूरत की वस्तुएं घर पर पहुंचाई जाएंगी।

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली में ऑपरेशन शिल्ड के तहत सील किए गए इलाकों की संख्या 30 हो गई है। सभी इलाकों में लोगों के बाहर आने जाने पर सख्त पाबंदी है। अब तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 903 हो चुकी है।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली का एक्शन प्लान तैयार किया है। यह प्लान सभी जिलों में विभाजित है। इस प्लान में यह रूपरेखा तैयार कर विभागों को दी गई है कि मामला मिलने के बाद कौन सी एंजसी क्या जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके बाकी पेज 8 पर

24 घंटे में 37 और लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

पिछले चौबीस घंटे में कोरोना विषाणु संक्रमितों और संक्रमण से मरने वालों की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन चौबीस घंटों में संक्रमितों की संख्या जहां 896 बढ़ी है, वहीं महामारी से जान गवाने वालों की संख्या में 37 की वृद्धि हुई है। शुक्रवार शाम तक देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 206 और संक्रमितों की संख्या 6,761 तक पहुंच गई। अभी 6,039 मरीजों का इलाज जारी है जबकि 515 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।

200 के पार पहुंची मरने वालों की संख्या

एक दिन में संक्रमण के 896 मामले, देश में अब तक की सबसे बड़ी संख्या

6 अप्रैल	7 अप्रैल	8 अप्रैल	9 अप्रैल	10 अप्रैल
704 मामले	508 मामले	485 मामले	591 मामले	896 मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार शाम पांच बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक चौबीस घंटे में मरने वालों में महाराष्ट्र के 25, दिल्ली के चार, पंजाब के तीन, आंध्र प्रदेश के दो, गुजरात का एक, झारखंड का एक और कर्नाटक का एक मरीज शामिल है। अब तक सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई हैं जिनकी संख्या 97 है। इसके बाकी पेज 8 पर

मूलचंद अस्पताल में मरीज व नर्स मिले संक्रमण के शिकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

मूलचंद अस्पताल में किडनी का इलाज करा रहे मरीज और एक नर्स को शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित पाया गया। दूसरी ओर, दिल्ली कैंसर संस्थान में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती मरीज की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई जबकि दो अन्य मरीजों को संक्रमित पाया गया है। उधर, कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए राममनोहर लोहिया अस्पताल के चार और डॉक्टरों को पृथक किया गया है।

राममनोहर लोहिया अस्पताल के चार और डॉक्टरों को पृथक किया गया

मूलचंद अस्पताल में बाकी पेज 8 पर

कोरोना के बाद अहम होगा भारत-जापान गठजोड़ : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और जापान के विशेष सामरिक व वैश्विक गठजोड़ कोविड-19 के बाद विश्व में नई प्रौद्योगिकी और समाधान विकसित करने में मदद कर सकते हैं। मोदी ने यह टिप्पणी जापान के अपने समकक्ष शिंजो आबे से टेलीफोन पर बातचीत के बाद किए एक ट्वीट में की। दोनों नेताओं ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। आबे के अलावा प्रधानमंत्री बाकी पेज 8 पर

यूपी में 4.81 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार डाले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रिक्शा चालक, ऑटोरिक्शा चालक, पल्लेदारों जैसे विभिन्न श्रेणी के 4,81,755 लाख दैनिक श्रमिकों को भरण-पोषण के लिए प्रति व्यक्ति एक हजार रुपए की राशि जारी की है। नगर विकास विभाग द्वारा चिह्नित इन श्रमिकों के लिए कुल 48,17,55,000 रुपए शुक्रवार को जारी किए गए। इस बीच, दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत 7242 मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड ने एक सप्ताह पहले भी 32,358 मजदूरों के खाते में सहायता राशि जारी की थी।

7242 पंजीकृत मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार देगी दिल्ली सरकार

उत्तर प्रदेश में बाकी पेज 8 पर

ईपीएफओ ने निपटाए पूर्णबंदी के दौरान 1.37 लाख पीएफ दावे

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पूर्णबंदी के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपए के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है।

श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बंदी के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपए के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है। इन बाकी पेज 8 पर

दरअसल

वधावन बंधुओं ने की खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा | कोरोना जंग में कोताही | अनुमति देने वाले प्रधान सचिव के खिलाफ जांच शुरू

वधावन परिवार को महंगी पड़ी तफरीह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

पूर्णबंदी के दौरान खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा करने वाले डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सरकार की विभिन्न जांच एजंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वधावन परिवार के सदस्यों को बंद के बीच निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र में सतारा जिले के महाबलेश्वर में हिरासत में लिया गया था। उन्हें अपने लेटरपैड पर यात्रा की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता को शुक्रवार को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक, गुप्ता की भूमिका की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक को सौंपी गई है।

पूर्णबंदी के दौरान वधावन बंधुओं और उनके परिजनों ने खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा की

अनुमति देने वाले प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू, अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया

अमिताभ गुप्ता

पुलिस ने कपिल, धीरज वधावन और उनके परिवार के सदस्यों समेत 21 अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। आइपीएस अधिकारी ने वधावन परिवार में किसी आपात स्थिति का हवाला देकर उसके सदस्यों को बंद के नियमों से छूट देने का पत्र जारी किया था। उनकी भूमिका को लेकर देशमुख ने ट्वीट किया, 'माननीय मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू होने वाली जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है।' वधावन परिवार की दो रेंज रोवर और तीन टोयोटा फार्चूनर भी ईडी ने जब्त की हैं।

'क्या धनवानों के लिए पूर्णबंदी नहीं'

विपक्षी भाजपा ने वधावन परिवार के सदस्यों को यात्रा की अनुमति दिए जाने की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'क्या महाराष्ट्र में अमीरों और धनवानों के लिए कोई बंदी नहीं है? कोई भी पुलिस की आधिकारिक अनुमति से महाबलेश्वर में छुट्टियां बिता सकता है।'

पुलिस ने बताया कि वधावन परिवार के सदस्यों को बंद के बीच निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र में सतारा जिले के महाबलेश्वर में हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने वधावन परिवार के सदस्यों समेत 23 लोगों को उनके फार्महाउस में पाया। दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुणे और सतारा- दोनों जिलों को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद वधावन परिवार के सदस्यों बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

ममता सूरत में शुक्रवार की दोपहर अपने बच्चे को गर्मी से बचाने की कोशिश करती मां।

'देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना का प्रसार नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

देश में कोरोना विषाणु के संक्रमण का प्रसार अभी तक सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी, तब हम ही सबसे पहले आपको बताएंगे। वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की ओर से जारी एक शोध पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

आइसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार गंभीर श्वास संक्रमण (एसएआरआइ) से पीड़ित कोरोना विषाणु संक्रमित कुल 104 मरीजों में से

40 मरीज ऐसे पाए गए जिन्होंने न विदेश यात्रा की थी और न ही वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे।

अग्रवाल ने कहा कि ये सभी मामले उन स्थानों से सामने आए हैं, जहां पहले ही संक्रमण मौजूद है। उन्होंने बताया कि कई बार संपर्कों को खोजने में सफलता नहीं मिलती है या फिर कर्मचारियों की ओर से पूरे प्रयास नहीं किए जाते हैं। ऐसे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि देश में संक्रमण सामुदायिक स्तर पर पहुंच गया है। आइसीएमआर ने 15 फरवरी से दो अप्रैल के बीच 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 52 जिलों में एसएआरआइ से पीड़ित 5,911 मरीजों की कोरोना विषाणु संक्रमण को लेकर औचक जांच की थी जिसमें यह निष्कर्ष सामने आया। जांच के वास्ते लिए गए कुल नमूनों में से 104 लोगों में (दो फीसद से कम) कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार एसएआरआइ से पीड़ित मरीजों के कोरोना विषाणु संक्रमण के चपेट में आने की संभावना 14 मार्च से पहले शून्य फीसद थी जो दो अप्रैल तक बढ़कर 2.6 फीसद हो गई।

एसएआरआइ सांस की एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज को निमोनिया हो सकता है या सांस रुक सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमित एसएआरआइ के मरीजों के उपचार के लिए पिछले महीने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।

देशबंदी के बीच बिना गाजे-बाजे के हुई शादी

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा)।

देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी के बीच भले ही लोग घरों के भीतर रहने को मजबूर है लेकिन शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर के शादी के इरादे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने परिवार एवं दोस्तों की गैर-मौजूदगी में बिना बैंड-बाजा-बारात के अपना विवाह संपन्न किया।

रामकिशन चव्हाण ने यहां कांदीवली उपनगर के एक मंदिर में अपनी प्रेमिका रीमा सिंह से गुरुवार को शादी की और इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया।

लंगर के दौरान तस्वीर खींचने व सेल्फी लेने पर रोक

जयपुर, 10 अप्रैल (भाषा)।

लंगर व राशन किट देते समय तस्वीर लेने के चक्कर में ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की घटनाओं को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों में तस्वीर लेने पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते के अनुसार पूर्ण बंदी में सामाजिक दूरी बनाए रखने व विषाणु के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नकाते ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि जिले में अन्नपूर्णा किट, तैयार खाने का पैकेट या लंगर वितरण के दौरान सेल्फी, तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाती है। इसका उल्लंघन होने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नकाते ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि जरूरतमंदों को भोजन, लंगर या भोजन पैकेट या राशन किट देते समय वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इससे सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन नहीं होता और संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नकाते ने कहा कि उनके आदेश का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूर्ण बंदी के दौरान धारा 144 और सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन नहीं हो। इसका एक संशोधित आदेश भी जारी किया जा रहा है। आदेश के अनुसार जिले में एनजीओ, भामाशाहों और दानदाताओं की ओर से जरूरतमंदों को अन्नपूर्णा किट या तैयार खाने का पैकेट या लंगर का वितरण किया जा रहा है। लेकिन कई बार इस दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित होती है।

मुफ्त जांच करने के लिए हमारे पास साधन नहीं : निजी प्रयोगशालाएं

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में करने का निर्देश दिए जाने के बाद कई प्रयोगशालाओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार 'तौर-तरीके बताएगी' जिससे वे देश में बढ़ती मांग के बीच जांच का काम जारी रख सकें।

कुछ निजी प्रयोगशालाओं के मालिकों ने यह भी कहा है कि उनके पास मुफ्त में यह महंगी जांच करने के लिए 'साधन नहीं' हैं। डॉ. डैंग्स लैब के सीईओ डॉक्टर अर्जुन डैंग ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं जिसका उद्देश्य कोविड-19 जांच की पहुंच बढ़ाने और इस आम आदमी के लिए वहनीय बनाना है।' उन्होंने दलील दी हालांकि निजी प्रयोगशालाओं के लिए कई चीजों की लागत तय है जिनमें अभिकर्मकों (रीएजेंट्स), उपभोग की वस्तुओं, कुशल कामगारों और उपकरणों के रखरखाव शामिल है।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच में भी संक्रमण नियंत्रण के कई उपाय करने पड़ते हैं जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, संक्रामक परिवहन तंत्र और साफ-सफाई की जरूरत। साथ ही हर वक्त कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

डैंग ने कहा, 'सरकार द्वारा तय 4500 रुपए की दर में निजी प्रयोगशालाएं बमुश्किल लागत निकाल पाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ तौर-तरीके लेकर आएगी जिससे निजी प्रयोगशालाओं में जांच का काम चलता रहे।' डैंग ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करते हुए हम अभी जांच मुफ्त कर रहे हैं और इस बारे में सरकार की तरफ से चीजों को और स्पष्ट किए जाने का इंतजार है।

डैंग की बातों से सहमति व्यक्त करते हुए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. ए वेलुमनी ने कहा, 'निजी प्रयोगशालाओं के पास यह महंगी जांच मुफ्त करने का साधन नहीं है।' उन्होंने कहा, 'यह सरकार का कर्तव्य है कि वह लागत का भुगतान करे, हम बिना लाभ के काम करेंगे।' वेलुमनी ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में संकेत दिया था, 'सरकार को कोई रास्ता तलाशना चाहिए और हम निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'सरकार अगर मदद नहीं करती है तो यह कोविड-19 से निपटने की दिशा में बड़ा झटका होगा।' गरीबों को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में निजी प्रयोगशालाओं को निर्देश दिया था कि उन्हें मुफ्त में कोरोना वायरस की जांच करनी चाहिए और मुश्किल की इस घड़ी में परोपकारी रुख अपनाना चाहिए।

सरकार ने कोरोना वायरस की जांच और पुष्टि परीक्षण के लिए 4500 रुपए कीमत तय की थी। शीर्ष अदालत ने सरकार से तुरंत इस दिशा में निर्देश जारी करने को भी कहा था। अदालत ने केंद्र की इस दलील को भी ध्यान में रखा था कि सरकारी प्रयोगशालाओं में यह जांच मुफ्त की जा रही है।

विदेश से चीनी लोगों के लौटने के बाद फिर बढ़ने लगे मामले

बेजिंग, 10 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना वायरस महामारी से दो महीने की जंग के बाद चीन में शुरू हुए उत्पादन कार्य के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आह्वान किया कि कोविड-19 के मद्देनजर कार्यस्थलों पर कड़ी सुरक्षा निगरानी रखी जानी चाहिए।

हालांकि, बड़ी संख्या में चीनी नागरिकों के विदेश से लौटने के साथ ही देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने शी के हवाले से कहा, 'अधिकारियों को कार्यस्थलों की सुरक्षा का कड़ाई से पालन करना चाहिए।'

चीन में कोरोना वायरस के 42 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या शुक्रवार को 81,907 हो गई।

ठीक हुए लोगों की फिर से जांच व निगरानी का काम तेज किया गया

इसके साथ ही देश में ठीक हुए लोगों की भी दोबारा जांच शुरू कर दी गई है, ताकि इस घातक वायरस के दोबारा लौटने के सारे रास्ते बंद किए जा सकें। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 42 लोगों में से 38 बाहर से आए लोग हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बाकी 47 ऐसे लोग वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें इसके कोई लक्षण नहीं थे। इनमें से 14 विदेश से आए लोग हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने शुक्रवार को बताया कि देश में कोविड-19 के 42 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 38 बाहर से आए संक्रमित लोग हैं। चीन ने देश में कोरोना वायरस का संकट फिर लौटने की चिंताओं के बीच कोविड-19 महामारी के ठीक हुए मरीजों की फिर से जांच करने और बिना लक्षण वाले मामलों को लेकर निगरानी तेज करने का गुरुवार को आदेश दिया। वुहान में 76 दिन से चला आ रहा लॉकडाउन हटने के एक दिन बाद इस कदम की घोषणा की गई है। वुहान से ही इस महामारी की शुरुआत हुई थी।

कोरोना संक्रमितों के ठहरने के कारण मस्जिद सील

गुवाहाटी, 10 अप्रैल (भाषा)।

असम की सरकार ने गुवाहाटी में एक मस्जिद को सील कर दिया है जहां पिछले महीने एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तीन लोग ठहरे थे और बाद में उनमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। यह जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी। सरमा ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनमें से दो असम लौटे थे। तीसरा उनके साथ अथगांव कब्रिस्तान मस्जिद में ठहरा हुआ था और उनमें से एक के साथ धुबरी गया था। मस्जिद में 12 मार्च को हुए समागम में कम से कम सौ लोगों ने हिस्सा लिया था और आयोजकों ने अभी तक 58 लोगों के नाम दिए हैं और उन सभी को पृथक वास में रखा गया है। उन्होंने कहा कि काफी बाद में हमारे संज्ञान में लाया गया कि कार्यक्रम हुआ था और हमने आयोजकों से कहा है कि इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों की सूची मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि मस्जिद को सील कर दिया गया है और इसे संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में 133 संवेदनशील इलाके चिह्नित

अमरावती, 10 अप्रैल (भाषा)।

आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 11 जिलों में 133 कोरोना वायरस प्रसार नियंत्रण क्षेत्रों को चिह्नित किया है। साथ ही उसने कोविड-19 की रोकथाम के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। कोविड-19 के लिए राज्य की नोडल अधिकारी अरजा श्रीकांत ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार महामारी के प्रसार को रोकने और लॉकडाउन प्रावधानों को कड़ा करने के लिए सभी कदम उठा रही है।

नेल्लोर जिले में सबसे अधिक 30 कोविड-19 प्रसार नियंत्रण क्षेत्र हैं। यहां कोरोना संक्रमण के 48 मामले सामने आए हैं।

सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

छिंदवाड़ा (मप्र), 10 अप्रैल (भाषा)।

जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक गांव में पूर्ण बंदी की अवहेलना कर सामूहिक तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने एक समुदाय के 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस निरीक्षक मुकेश द्विवेदी ने बताया कि जिले के चौरई तहसील के खैरीखुर्द गांव में गुरुवार रात एक मस्जिद में गांव के सरपंच सहित 40 लोग पूर्ण बंदी का उल्लंघन कर सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हुए मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस को पूर्ण बंदी का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस के गश्ती दल द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 (पांच या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध), भादंवि की धारा 188 (सरकारी सेवक के कानूनी आदेश की अवहेलना), धारा 269 (उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मध्य प्रदेश जन सुरक्षा कानून 1949 की संबद्ध धाराएं भी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई और बाद में वहीं मौके पर जमानत पर छोड़ दिया गया। द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में 64 विदेशियों सहित 74 जमातियों पर मामले

भोपाल, 10 अप्रैल (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें 64 विदेशी तथा 10 अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ कोरोना संक्रमितों का यहां विभिन्न अस्पतालों में उपचार भी चल रहा है और ये सभी लोग पिछले माह निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से यहां ठहरे हुए हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रजत सकलेचा ने शुक्रवार को बताया कि इनके अलावा पुलिस ने इन जमातियों को शहर की अलग अलग मस्जिदों में शरण देने वाले 13 स्थानीय लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। इन लोगों ने इस हरकत से जानलेवा कोरोना महामारी के फैलने की आशंका है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये जमाती शहर की अलग-अलग मस्जिदों में रहते रहे तथा इन्होंने यह भी छुपाया कि इन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों को स्वयं सामने आने अन्यथा इसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने जमात में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

एएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शहर के पांच अलग अलग पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है क्योंकि ये अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे।

देश में है हाइड्रॉक्सि क्लोरोक्वीन का पर्याप्त भंडार : सरकार

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

भारत में गर्मियों की दस्तक से भले ही उम्मीदें जगी हों कि गर्म व नम मौसम में कोविड-19 वैश्विक महामारी का असर धीमा हो जाएगा लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मौसमी बदलाव के प्रति कोरोना वायरस की संवेदनशीलता को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान, अभियांत्रिकी व आयुर्विज्ञान अकादमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रायोगिक अध्ययन निश्चित ही लैबोरेटरी में अधिक तापमान व नमी के स्तर और सार्स-सीओवी-2 के जीवित रहने की संभावना घटने के बीच संबंध दिखाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरणीय तापमान, नमी और किसी व्यक्ति के शरीर के बाहर वायरस का जिंदा रहने के अलावा कई और कारक हैं जो 'असल दुनिया' में मनुष्यों के बीच संक्रमण की दर को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। सात अप्रैल को तैयार त्वरित विशेषज्ञ परामर्श रिपोर्ट का लक्ष्य वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत मुहैया कराना है जो सार्स-सीओवी-2 के मौसमी परिवर्तन की क्षमता को लेकर फैसला लेने में प्रासंगिक हो। विशेषज्ञों ने कहा कि अब तक उपलब्ध लैबोरेटरी डाटा दर्शाते हैं कि ज्यादा तापमान और तापमान संवेदनशीलता में भिन्नता पर सार्स-सीओवी-2 के जिंदा रहने की संभावना कम होती है हालांकि यह सतह के उस प्रकार से काम करने पर निर्भर करता है जिस पर वायरस को रखा गया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस विषय पर अब तक उपलब्ध नियंत्रित अध्ययनों की संख्या कम है। इसमें कहा गया कि प्रायोगिक अध्ययनों से आए परिणाम के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण स्थितियां हैं।

इस्तीफा दे चुके आइएएस अफसर ने ड्यूटी पर लौटने से इनकार किया

अमदाबाद, 10 अप्रैल (भाषा)।

आठ महीने पहले इस्तीफा दे चुके पूर्व आइएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ को सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण बने हालात को देखते हुए तत्काल ड्यूटी पर आने का निर्देश दिया लेकिन अधिकारी ने कहा कि वे काम पर नहीं लौटेंगे।

बताते चलें कि गोपीनाथ ने 'जम्मू-कश्मीर के लोगों को आजादी नहीं देने' के विरोध में इस्तीफा दिया था। सरकार का तर्क है कि अधिकारी का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है इसीलिए उन्हें ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। गोपीनाथ का कहना है कि ड्यूटी पर बुलाकर सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। कोरोना संकट में वे सेवाएं देने को तैयार हैं लेकिन एक आइएएस अधिकारी के रूप में नहीं। पिछले वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां लगाने और राज्य को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के विरोध में 33 वर्षीय कन्नन ने इस्तीफा दिया था। वे दमन और दीव में पदस्थ थे। कन्नन ने ट्वीट किया, 'मैं जानता हूं कि वे मुझे और प्रताड़ित करना चाहते हैं।'

गर्म मौसम में कोरोना के असर को कम बताने वाले अध्ययन निर्णायक नहीं

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

भारत में गर्मियों की दस्तक से भले ही उम्मीदें जगी हों कि गर्म व नम मौसम में कोविड-19 वैश्विक महामारी का असर धीमा हो जाएगा लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मौसमी बदलाव के प्रति कोरोना वायरस की संवेदनशीलता को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान, अभियांत्रिकी व आयुर्विज्ञान अकादमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रायोगिक अध्ययन निश्चित ही लैबोरेटरी में अधिक तापमान व नमी के स्तर और सार्स-सीओवी-2 के जीवित रहने की संभावना घटने के बीच संबंध दिखाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरणीय तापमान, नमी और किसी व्यक्ति के शरीर के बाहर वायरस का जिंदा रहने के अलावा कई और कारक हैं जो 'असल दुनिया' में मनुष्यों के बीच संक्रमण की दर को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। सात अप्रैल को तैयार त्वरित विशेषज्ञ परामर्श रिपोर्ट का लक्ष्य वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत मुहैया कराना है जो सार्स-सीओवी-2 के मौसमी परिवर्तन की क्षमता को लेकर फैसला लेने में प्रासंगिक हो। विशेषज्ञों ने कहा कि अब तक उपलब्ध लैबोरेटरी डाटा दर्शाते हैं कि ज्यादा तापमान और तापमान संवेदनशीलता में भिन्नता पर सार्स-सीओवी-2 के जिंदा रहने की संभावना कम होती है हालांकि यह सतह के उस प्रकार से काम करने पर निर्भर करता है जिस पर वायरस को रखा गया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस विषय पर अब तक उपलब्ध नियंत्रित अध्ययनों की संख्या कम है। इसमें कहा गया कि प्रायोगिक अध्ययनों से आए परिणाम के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण स्थितियां हैं। अकादमी के मुताबिक पहली स्थिति प्रयोगशाला की स्थितियों का वास्तविक दुनिया की स्थितियों से संबंधित होना है।

रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक प्राकृतिक इतिहास अध्ययनों में संभावित मौसमी प्रभावों के संबंध में विरोधाभासी परिणाम भी हैं। विशेषज्ञों ने पाया कि यह रिपोर्ट असंतोषजनक डेटा गुणवत्ता, संदेहास्पद कारकों और अपर्याप्त समय के कारण भी प्रभावित है।

मुस्तैदी गांव की माताओं और बेटियों ने उठाई जिम्मेदारी, प्रवेश के रास्तों को कंटीले तारों से बंद किया

लाठियां लेकर मोर्चे पर डटीं महिलाएं

चट्ठा पिंड (जम्मू), 9 अप्रैल (भाषा)।

जम्मू में निवासियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए अपने गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने और पूर्णबंदी सुनिश्चित करने के लिए एक गांव की महिलाओं ने लाठियों के साथ प्रवेश केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने गांव में प्रवेश के रास्तों को कंटीले तारों से बंद कर दिया है।

जम्मू में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर गांव में माताओं और बेटियों ने यह काम संभाला है। जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस से बुधवार को मौत हो गई। इससे जम्मू कश्मीर में इस संक्रामक रोग से मरने वाले लोगों की संख्या चार हो गई है। यह जम्मू क्षेत्र में मौत का पहला मामला है क्योंकि अन्य तीन लोगों की मौत कश्मीर में हुई है।

जम्मू में अभी तक 36 लोग संक्रमित पाए गए हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के 188 मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को 24 मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों से पूर्व

सरपंच गुरमीत कौर के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक अपने गांव की सुरक्षा में तैनात रहता है। 6,500 से अधिक आबादी वाले इस इलाके के प्रवेश केंद्रों को कंटीली तारों से बंद कर दिया गया है।

कौर ने बताया, 'कोविड-19 जानलेवा बीमारी है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में अपने पुलिस बल और सरकार का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने अपने छोटे-से इलाके की सुरक्षा करने और बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने का जिम्मा लिया है।' उन्होंने बताया कि जागरूकता के बावजूद कुछ लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और घूम रहे हैं जिससे न केवल वे संक्रमित हो सकते हैं बल्कि उनका परिवार और इलाके के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। कौर (55) ने कहा कि पुलिस बंदी सुनिश्चित करने के लिए गांवों, इलाकों या गलियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इलाके की रक्षा करने और पुलिस को राहत देने में थोड़ा योगदान दें जो बंद के इस समय में बड़े पैमाने पर ड्यूटी कर रही है। कम से कम हम अपने इलाके की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं।'

www.readwhere.com

खतरे को देखते हुए सांस मरीजों की होगी कोरोना जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

देश में सांस के मरीजों में किए कोरोना परीक्षण में कई मरीजों में संक्रमण की पुष्ट हुई है। इसके बाद से सरकार ने सांस की तकलीफ वाले वार्ड में भर्ती सभी मरीजों में कोरोना की जांच करने को कहा गया है। कई सांस या दूसरी तकलीफों के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों में कोरोना की पुष्टि के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।

जांच के लिए बनी नई रणनीति में तय किया गया है कि सभी रोगसूचक व्यक्ति जिन्होंने हाल में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की है उनकी तो जांच की ही जाएगी जो प्रयोगशाला के सभी रोगसूचक संपर्क मामलों की पुष्टि करते हैं उनकी भी जांच की जाएगी। कोरोना के इलाज में लगे सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता गंभीर या तीव्र श्वसन बीमारी (बुखार और खांसी के साथ सभी सांस संबंधी मरीजों की भी जांच की जाएगी। एक पुष्ट मामले के प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क में आए सभी लोगों का परीक्षण किया जाएगा। यह जांच कब की जानी चाहिए इसके बारे में निर्देश में लिखा है। एक बार संक्रमित के संपर्क में आने के पांच दिन और दिन 14 के बीच जांच कराएं।

सभी संदिग्धों जिनमें लक्षण (बुखार, खांसी, गले में खराश, बहती नाक) दिखे उनको बीमारी के सात दिनों के भीतर जांच कराने को कहा गया है। अगर कोरोना की पुष्टि हुई हो तो बीमारी के सात दिनों के बाद एंटीबॉडी परीक्षण किया जाए।

‘ऑपरेशन शील्ड’ से दिलशाद गार्डन में तोड़ा कोरोना का क्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

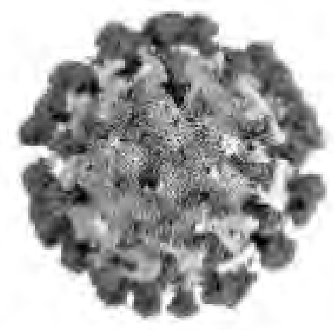

दिल्ली में कोरोना

कुल मामले :	903
नए मामले :	183
ठीक हुए :	27
मौत:	14

दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिलशाद गार्डन में पिछले 10 दिन से कोई नया मामला नहीं

दिल्ली सरकार के ‘ऑपरेशन शील्ड’ से सबसे पहले दिलशाद गार्डन के लोगों को फायदा हुआ है। पहली बार दिलशाद गार्डन में 8 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। बाद में 15 दिन की मेहनत से क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से मुक्त किया है। अब 10 दिन से दिलशाद गार्डन में कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि दिलशाद गार्डन में एक महिला और उसके बेटे में सऊदी अरब से लौटने पर कोरोना पाया गया था। महिला का इलाज करने वाले मोहल्ला क्लीनिक डॉक्टर समेत 7 लोग कोरोना पीड़ित हो गए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। महिला के संपर्क में 81 को चिन्हित किया गया। दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में 123 मेडिकल टीमों का गठन किया गया।

इन टीमों ने 4032 घरों में रहने वाले 15 हजार से अधिक लोगों की जांच की। दिल्ली सरकार 15 हजार लोगों को फोन कर कोरोना के संबंध में जानकारी ले रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसएलके नायक ने बताया महिला ने जांच में सहयोग किया, लेकिन उनके बेट ने नहीं बताया कि वह इस दौरान कहां-कहां गया और किन लोगों से मिला। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला और उसका बेटा जिन-जिन लोगों से मिला, उन सभी लोगों को चिंहित करते हुए उन्हें क्वारंटाइन किया गया। पुलिस से भी संपर्क कर दिलशाद गार्डन व पुरानी सीमापुरी इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दोनों क्षेत्र में लोगों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। पुरानी सीमापुरी को इसलिए सील किया गया, क्योंकि महिला के संपर्क में आने से मोहल्ला क्लीनिक का डॉक्टर भी कोरोना से पीड़ित हो गया था। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई 123 मेडिकल टीमों को 50-50 घरों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने 4032 घरों में 150 हजार से अधिक लोगों की जांच की। जिनको भी कोई परेशानी थी, उसे तत्काल एंबुलेंस से आरएमएल अस्पताल भेज दिया जाता था। 15 से अधिक दिनों की लगातार मेहनत और लगन का परिणाम सकारात्मक निकला है।

मरकज में जानकारी छिपाने के कारण प्राथमिकी दर्ज

कांग्रेस की महिला पार्षद समेत पति और बेटी भी संक्रमित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

दिल्ली में एक कांग्रेसी पार्षद के पति पर कोरोना बीमारी से जुड़ी जानकारी छिपाने और गलत व्यवहार करने पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पार्षद पति के साथ महिला पार्षद और बेटी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जांच में पुलिस को पता चला कि पार्षद पति निजामुद्दीन के मरकज में भी गए थे। छावला थाना में धारा 188, 269 आदि के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वजह से पूरे दीनपुर गांव को सील कर दिया गया है।

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच छावला थाने के दीनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कांग्रेस पार्षद के पति को निगरानी में रखा था। लेकिन जांच के दौरान वह घर में नहीं पाया गया। उनके फोन से और परिजनों से जानकारी ली गई तो पता चला कि वह निजामुद्दीन के मरकज में भी गए थे। हालांकि उन्होंने जमात में जाने की बात पुलिस से छिपा ली थी। पुलिस ने जांच में दो परिवार के सदस्य को भी संक्रमित पाया है। पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की है। उन्हें अभी आंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया है।

बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद, पुलिस ने उससे पूछताछ कर, कहीं आने जाने या किसी से मिलने को लेकर जानकारी मांगी थी। उसने किसी से भी मिलने या कहीं आने जाने को लेकर पुलिस को इनकार कर दिया था। वह दीनपुर गांव में परिवार के साथ रहते हैं। इस वजह से पूरे गांव को सील कर दिया गया है। इनकी पत्नी और बेटी भी बाद में संक्रमित मिलीं जिनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके द्वारा दीनपुर गांव के कई जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ वितरित करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक जांच में कोई फोटो, वीडियो नही मिला है, न ही इसके बारे में पता चला है।

महाराजा अग्रसेन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर के कोरोना पीड़ित होने की जानकारी प्रशासन से छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम के जांच के बाद एपिडेमिक एक्ट के तहत यह एफआइआर दर्ज कराई गई है।

मुस्तैद डॉक्टरों के भी वेतन में कटौती, विरोध शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

राजधानी के एम्स, राम मनोहर लोहिया व सफदरजंग के डॉक्टरों ने करोना के लिए उनके वेतन में से पैसा काटने के आदेश का विरोध किया है। डॉक्टरों ने अपने-अपने अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनों के माध्यम से अपना विरोध अस्पताल प्रशासन व उच्च अधिकारियों के सामने जताया है।

रामनोहर लोहिया अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री कोरोना राहत कोष के लिए चिकित्सकों का एक दिन का वेतन काटे जाने के आदेश का विरोध किया है। आरएमएल रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ निर्मल महापात्र ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को लिखे पत्र में इसका विरोध करते हुए कहा है कि चिकित्सक तो पहले ही अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं ऐसे में उनको तो जोखिम भत्ता मिलना चाहिए न कि मिल रहे वेतन को ही काटा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि चिकित्सकों का वेतन न काटा जाए। उधर, सफदरजंग के रेजीडेंट डॉक्टरों ने भी इस तरह के कदम की कड़ी आलोचना की है। सभी ने वेतन काटने का विरोध किया है।

एम्स रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पहले ही इसका विरोध किया है। चिकित्सकों का कहना है कि एक ओर प्रधानमंत्री डॉक्टरों को योद्धा बताते हुए इनका अभिनंदन करने की बात कर रहे हैं दूसरी ओर जोखिम के काम में लगे चिकित्सकों का वेतन काटने की बात हो रही। यह निहायत ही हास्यास्पद है। एम्स आरडीए के डॉ श्रीनिवास का कहना है कि डॉक्टर कोरोना मरीजों के लए जो सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं वह कर रहे हैं उनका इलाज करके और योगदान क्या और क्यों हो।

सांसद ने एलएनजेपी अस्पताल में दी पीपीई किट

पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार के कहने पर 1000 पीपीई किट एलएनजेपी अस्पताल को उपलब्ध कराए हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार को और भी पीपीई किट की जरूरत है, तो वे और भी किट मुहैया करवाने को तैयार हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में भी लोगों को राशन और खाना उपलब्ध करवा रहे है। इस संकट की घड़ी में जितनी भी मदद आम जनता को उपलब्ध करा सकते हैं वह मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लंघन देशबंदी के बाद भी दिल्ली के रघुबीर नगर में लोग कुछ इस तरह सड़क पर इकट्ठा नजर आए।

निगमों की हेल्पलाइन पर परामर्श ले रहे लोग

घर बैठे बढ़ रहा तनाव, पूछ रहे समाधान

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

कोरोना संक्रमण पर 21 दिनों की पूर्णबंदी और दिल्ली में लगे धारा 144 में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग जहां दिल्ली पुलिस को सहायता के लिए फोन कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर इससे हटकर घरों में बंद लोग तनाव को दूर भगाने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे कई उपायों के बारे में मार्गदर्शन मांग रहे हैं।

ऐसे करीब 4953 नागरिकों से कॉल प्राप्त हुए हैं। इस मांग पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का आयुष विभाग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, तनाव प्रबंधन, प्रतिरक्षा बढ़ाने, आहार, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में आयुष डॉक्टरों के माध्यम से नागरिको को मुफ्त टेलीफोन परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।

पीसीआर बन रही गर्भवती महिलाओं का सहारा

पीसीआर को प्रसव पीड़ा से परेशान महिलाओं को अस्पतालों में भर्ती कराने का अनुरोध मिल रहा है। पीसीआर के पुलिस उपायुक्त शरत कुमार सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को ही 38 महिलाओं को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रात 11 बजे के बाद पूर्वी दिल्ली में चार, दक्षिणी में आठ, दक्षिण पूर्वी में दो, बाहरी दिल्ली में चार, उत्तर पश्चिमी में तीन, उत्तर पूर्वी में दो, शाहदरा में दो, उत्तरी में दो ,द्वारका में एक महिलाएं पुलिस को सहायता की मांग की जिसे तुरंत गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया।

निगम के सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक योगेंद्र सिंह मान ने बताया कि आयुष विभाग विद्यालयों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर स्कूली बच्चों और अभिभावकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श दे रहा है। आयुष विभाग के निदेशक आयुर्वेद के माध्यम से जागरूकता फैलाने और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आनलाइन सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं। निगम ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच नागरिकों को तक सुविधा पहुंचाने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन शुरू की हैं। हेल्पलाइन लोगों को अकेले होने के संकट और भय से निपटने में मदद कर रही है। निगम ने विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो उन्हें सहायता, भोजन, भावनात्मक समर्थन और किसी विशेष आवश्यकता की व्यवस्था करने के संदर्भ में सहायता प्रदान कर रही है।

कोरोना से डरे मजदूरों की मांग, ‘करो ना कुछ’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

पूर्णबंदी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों सहित 43 करोड़ श्रमिकों के लिए 5000 प्रति माह देने की मांग को लेकर मजदूर संगठनों और समाजिक संगठनों ने शुक्रवार को ‘करो ना कुछ’ अभियान चलाया। कोरोना प्रकरण की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के लिए खड़ी हुई जीवन यापन की समस्या पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक दिन का अभियान जनआंदोलन की राष्ट्रीय समन्वय के बैनर तले चला। इस अभियान से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सामूहिक उपवास रखा और सरकारों से मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों को लेकर संवेदनशील रुख अपनाने और उनके लिए जरूरी आर्थिक मदद जारी करने की मांग की।

जन आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वय के मुताबिक इस मुहिम को 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुराई स्वामी से लेकर 97 साल के डॉ जीजी पारिख और प्रख्यात लेखक रामचंद्र गुहा तक का समर्थन मिला। इसके अलावा कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व उप-सभापति बीआर पाटिल, प्रसिद्ध गांधीवादी प्रसन्ना, राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष गणेश देवी, जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय और नमर्दा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर आदि भी समर्थन में उतरे हैं।

उनकी मांग है कि केंद्र सरकार सभी 43 करोड़ जरूरतमंदों को 5000 रुपए प्रतिमाह की व्यवस्था करें। राज्य सरकारें मजदूर संगठनों की ओर से लगातार की जा रही मांगों को लागू करे जिनपर केंद्रीय गृह व श्रम मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श जारी किया गया है। इस बाबत जारी एक साझा बयान में आयोजक जन आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वय ने कहा कि भूख का समंदर बहुत बड़ा है और हमारा आंदोलन उसमें बहुत छोटा किंतु महत्त्वपूर्ण है। इस पूर्णबंदी का सबसे असर बेघर व भिखारी लोगों पर पड़ा है। साथ ही इस प्रकोप ने प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेका मजदूरों, निर्माण मजदूरों, दैनिक मजदूरों के रोजगार का स्रोत खत्म कर दिया है।

घर से भुगतान के तरीके सिखा रहीं बिजली कंपनियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

कोरोना संक्रमण के बीच बिजली भुगतान केंद्रों से उपभोक्ताओं की भीड़ खत्म करने के लिए बिजली कंपनियां अब लोगों को घर बैठे ही बिल भुगतान के तरीके सिखा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं के एसएमएस व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से सूचनाएं दी जा रही है। यह पहल दिल्ली की बिजली कंपनी टाटा पॉवर ने शुरू की है। कंपनी के पास पंजीकृत सभी मोबाइल पर ये संदेश भेजे जा रहे हैं।

टाटा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिल भुगतान के लिए इन जगहों पर आने की जरूरत नहीं है। भीड़ की वजह से परेशानी पैदा न हो इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता ऑनलाइन विकल्प जैसे वेबसाइट, यूपीआई, ई-वॉलेट, मोबाइल ऐप से भुगतान कर सकते है।

15 सेकेंड में होंगे पूरी तरह संक्रमण रहित

मंडी में प्रवेश करने से पहले गुजरना होगा मशीन से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल ।

आजादपुर मंडी में आने वाले खरीदारों को कोरोना संक्रमम से बचाने के लिए विषाणुरोधी मशीनों को लगाया गया है। इनके अंदर आने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर पर विषाणुरोधी दवा का छिड़काव होगा। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को इसकी शुरूआत की। ये मशीन आजादपुर मंडी के गेट नंबर एक और पांच पर लगाई गई हैं। अब मंडी में दाखिल होने के लिए इनके अंदर से गुजरना अनिवार्य हो गया है।

गोपाल राय ने बताया कि क्योंकि सब्जियां आवश्यक वस्तुओं में आती हैं इसलिए मंडी को खोले रखना आवशअयक है। यहां आने वाले व्यापारियों और मजदूरों को कोरोना विषाणु से संक्रमित होने का खतरा लगातार बना हुआ था। दिल्ली आइआइटी द्वारा विकसित की गई मशीन को आजादपुर मंडी के गेट नंबर एक और पांच पर लगाया गया है। एक मशीन को विकसित करने में 1.5 लाख रुपये की लागत आई। अब मंडी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस मशीन से गुजरना होगा। इसके अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति पर सोडियम हाइपोक्लोराइट की बौछार की जाती है, जिसके बाद वह पूरी तरह से विषाणुमुक्त हो जाता है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली की अन्य मंडियों में भी यह मशीन लगाई जाएगी। इस मौके पर आजादपुर मंडी के अध्यक्ष आदिल अहमद खान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

इस मशीन में प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापीय परीक्षण होगा। जिनका तापमान समान्य है, उन्हें इस मशीन से गुजारा जाएगा। इस मशीन से गुजरते ही व्यक्ति के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइट युक्त विषाणुनाशक की फुहार शुरू हो जाएगी। मशीन से गुजरते ही संबंधित व्यक्ति पूरी तरह विषाणुमुक्त होकर संक्रमणरहित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 12 से 15 सेकेंड का समय लगता है। इस तरह संक्रमण का खतरा दूर हो जाएगा है। एक दो दिन की मॉनिटरिंग के बाद इस मशीन को दिल्ली की सभी मंडियों में लगाया जाएगा।

संक्रमणरोधी सुरंग से निकलते मंत्री गोपाल राय।

मंडी के गेट नंबर एक और पांच पर लगाई गई मशीन

आइआइटी द्वारा 1.5 लाख रुपए की लागत से बनाई गई मशीन

लोगों को केवल आवेदन रसीद, राशन कार्ड नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

6.5 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उनके पास केवल आवेदन की रसीद है, राशन कार्ड नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर उन परिवारों तक राशन पहुंचाने का आग्रह किया।

उन्होंने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को खाद्य सामग्री की कोई दिक्कत ना हो इसलिए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा। महामारी के इस संकट के समय में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग सबसे ज्यादा जरूरतमंद है।

इलाज के इंतजार में सड़कों पर मरीज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। इलाज के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली के बड़े अस्पताल एम्स में आया था, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही लॉकडाउन हो गया। अब यहां सड़कों पर दिन और रात काट रहे हैं। एकदम बेघर महसूस कर रहे हैं। ये कहना है विजय सहाय का। विजय सहाय अपने 13 साल के बच्चे का इलाज कराने मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हैं।

यह परेशानी केवल पेशे से किसान विजय की ही नहीं है। बल्कि विजय जैसे कई परिजन व मरीज जो विभिन्न राज्यों से एम्स व सफदरजंग इलाज कराने आए हैं अब अधर में लटके हैं। इन मरीजों का दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं है, जिससे वे दिल्ली के एम्स व सफजरजंग अस्पतालों के बीच की सड़क अरविंद मार्ग के किनारे और इसके सब वे में बने आश्रय व रैन बसेरों में दिन गुजार रहे हैं। इनमें से किसी को कैंसर, किसी को किडनी तो किसी को हृदय संबंधी रोगों या अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज का इंतजार है।

देशभर में लागू 21 दिन के बंद में फंसे सहाय को मुफ्त इलाज के लिए मदद पाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाला पीएपीएल कार्ड चाहिए, लेकिन वह भी गांव में है। कम से कम दवा तो मिल जाती। अब कार्ड मंगवा भी नहीं सकता क्योंकि डाक भी बंद है। विजय सहाय कहते हैं कि मैं 15 मार्च से यहां हूं। एम्स के डॉक्टरों ने कुछ दवाएं लिखीं लेकिन वो बहुत महंगी हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरे पास बीपीएल कार्ड है तो मुझे दवाएं खरीदनी नहीं होंगी। इसी टेंट में रहते हैं, जम्मू से आए 22 साल के अमनजीत। पिछले साल अक्तूबर में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए अमन जीत को इलाज के लिए एम्स भेजा गया था। इनको डर है कि कहीं हाथ जाम ही न हो जाए। अपने पिता के साथ यहां आए अमनजीत ने कहा कि यहां ना तो जांच हो रही है और ना ही इलाज हो रहा है। हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है। । उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की रहने वाली 34 साल की रेखा देवी को कैंसर है। वह होली से पहले ही अपने पति सुरजीत श्रीवास्तव के साथ इलाज कराने के लिए यहां आ गई थीं। एक महीने बाद भी रेखा जस की तस स्थिति में हैं। इलाज के मामले में अभी कोई शुरूआत नहीं हुई है और घर जाने के सारे रास्ते बंद हैं।

www.readwhere.com

जमातियों को शरण देने और देशबंदी के उल्लंघन का आरोप

पांच महिलाओं समेत 13 के खिलाफ मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 अप्रैल।

थाना सूरजपुर पुलिस ने देशबंदी का उल्लंघन व जमातियों को शरण देने पर पांच महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपी जमातियों को शरण देने के साथ ही उनको सार्वजनिक स्थान पर भी लेकर गए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसने किसी ना किसी रूप में जमातियों की मदद की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

एसीपी पीपी सिंह ने बताया कि पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के बेगमपुर गांव में कुछ लोगों ने जमातियों को शरण दी थी तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ले गए। जांच में मामला सही पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर सलीम अहमद ने पांच महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा-188 व धारा-144 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कराया गया है। आरोपियों ने गांव में 10 जमातियों को शरण दी थी। एसीपी ने बताया कि नामजद आरोपियों में इमाम मोहम्मद, राज मोहम्मद, नाजिम निवासी ग्राम बेगमपुर सूरजपुर, सरफराज, सलीम, रशीद मकबूल निवासी उस्मानीबाद महाराष्ट्र, गफूर निवासी बीड महाराष्ट्र, शेख कय्यूम निवासी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, श्फरद्दीन उस्मानाबाद महाराष्ट्र, नूरजहां उस्मानाबाद महाराष्ट्र, शरीफा बी. पत्नी रशीद मकबूल, अहमदाबी पत्नी गफूर खां व रुकिया बी. पत्नी शेख कय्यूम आदि शामिल हैं।

अगर तब्लीगी के संपर्क में आए हैं तो स्वेच्छा से कराएं जांच, नहीं तो होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

जो दिल्ली में तब्लीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हो या किसी जमाती के संपर्क में आए लोग, या जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना है, वे बिना देरी किए स्वेच्छा से 24 घंटे के अंदर चिकित्सकीय जांच के लिए मुख्य चिकित्सकाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। उपस्थित नहीं होने पर महामारी अधिनियम 1987 की धारा 2,3,4 एवं उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में पूर्णबंदी लागू है। इस संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है। इसमें थोड़ी से लापरवाही या चूक होने पर इसका संक्रमण अत्यंत तीव्र गति से होता है। बीमारी से मृत्यु की संभावना भी है। ऐसे में जो लोग भी तबलीगी जमात से आए है या फिर संपर्क में आए हो या किसी भी संक्रमित के संपर्क में आए हो वह स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सीय जांच के लिए सीएमओ के सम्मुख स्वेच्छा से उपस्थित हो।

गौतमबुद्धनगर में 86 में से 85 की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कराने का निर्णय लिया है। जो मरीज संक्रमित हैं, उन्हें तुरंत पृथक कर दिया जाए। वहीं, गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार को 86 लोगों की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली है। इसमें 85 लोगों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। उनमें कोरोना विषाणु का संक्रमण नहीं पाया गया है। वहीं, सेक्टर- 50 में रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एपी चतुर्वेदी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना विषाणु से संबंधित 86 लोगों की जांच रिपोर्ट मिली है। जिसमें से 85 लोगों में रिपोर्ट नकारात्मक आई है। सेक्टर-50 के रहने वाले एक व्यक्ति के भीतर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पुष्ट मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर-50 में पुष्ट रोगियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गत गुरुवार को भी सेक्टर-50 में एक व्यक्ति में कोराना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ऐसे में सेक्टर-50 को संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

देशबंदी का उल्लंघन करने पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 अप्रैल।

शासन व प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी कुछ लोग देशबंदी का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठी होने पर थाना जारचा पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी लोग सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के कलौंदा गांव में मुस्लिम समाज के कुछ लोग एकत्र होकर घर से बाहर जा रहे थे।

देशबंदी होने के बाद भी भीड़ इकट्ठी कर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। नियमों का उल्लंघन करने पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी का कहना है कि आशंका है कि आरोपी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे।

निगरानी और जांच टीम पर लगा खानापूर्ति करने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

जिले में कोरोना विषाणु के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से निगरानी और नियंत्रण टीम का गठन किया गया है। ऐसी 300 टीमों में 900 कर्मचारी शामिल हैं। जांच के नियमानुसार प्रत्येक टीम को घरों में जाकर सदस्यों के स्वास्थ्य का जांच करेगी।

लक्षण दिखने पर पृथक रहने की सलाह देगी, लेकिन शहर में कई जगहों पर इन कर्मचारियों पर महज खानापूर्ति करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शुक्रवार को भी शहर के कई सेक्टरों में पहुंचे टीम के सदस्यों ने लोगों का नाम पूछा और किसी के बीमार होने की महज मौखिक जानकारी पूछी, इसके बाद आगे बढ़ गए। सेक्टर-41 निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि शुक्रवार सुबह जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दो आशा कर्मचारी उनके घर पहुंची थीं। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का नाम पूछा और फिर किसी को बुखार तो नहीं है, यह पूछने के बाद टीम आगे बढ़ गई। लोगों ने जब इस सर्वेक्षण के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि संवेदनशील इलाकों के सभी निवासियों की स्क्रीनिंग हो रही है।

आरोप यह भी है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास तापीय परीक्षण (थर्मल स्कैनर) भी नहीं थे और सभी कर्मचारी बिना पीपीई के जांच करने निकले थे। ऐसी शिकायत मिलने पर सीएमओ डॉ. एपी चतुर्वेदी ने बताया कि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है।

अगर ऐसा है तो टीम के कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही सभी को थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टीम के सदस्यों को बारीक जांच करनी है।

मास्क के बगैर निकले 137 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

दिल्ली में बगैर मास्क पहने बाहर निकलने पर 137 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। बता दें कि गुरुवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था। राजधानी में बिना मास्क पहनकर चलना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से इसे कानून अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके कारण बिना मास्क निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है।

शुक्रवार को ऐसे 137 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 32 मामले उत्तर पश्चिम जिला, 23 मामले दक्षिण जिला, 20 मामले उत्तर जिला और 14 मामले बाहरी जिला में दर्ज किए गए हैं। इनके खिलाफ आइपीसी के सेक्शन 188 के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। उधर, देशबंदी की घोषणा हुए 17 दिन बीत चुके हैं लेकिन राजधानी में कुछ लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे 155 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने आइपीसी की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

जागरूकता

कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए एक बच्चा।

महिला के वीडियो पर आपत्तिजनक ऑडियो लगा किया वायरल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

एक निजी चैनल की न्यूज एंकर ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला साइबर थाने में दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि किसी ने उनके वीडियो को ट्विटर एकाउंट से लेकर उस पर आपत्तिजनक ऑडियो लगाकर अपलोड कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता एक निजी चैनल की एंकर है। सेक्टर-45 में रहने वाली एंकर ने बताया कि 2018 में दिवाली के मौके पर उन्होंने अपना एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था।

हरियाणा सरकार ने कसी कमर, कोरोना मरीजों के लिए बनाए अलग अस्पताल

फरीदाबाद, 10 अप्रैल (जनसत्ता)।

कोरोना विषाणु महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार के साथ प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के लिए कोविड-19 अस्पताल अलग से घोषित किए हैं। इसी के तहत फरीदाबाद में एनआइटी-3 के ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को विशेष तौर से कोरोना विषाणु संक्रमित पीड़ितों के लिए तैयार किया गया है। इस अस्पताल में फरीदाबाद और पलवल जिले के कोरोना संक्रमण से बीमारों का इलाज होगा। दोनों जिलों के संक्रमितों को यहां इलाज किया जाएगा। यहां पर बिस्तर कम पड़ने की हालत में ही मरीज दूसरे अस्पतालों में भेजे जाएंगे। फिलहाल इस अस्पताल में पांच मरीज भर्ती हैं। इनमें चार ग्रीनफील्ड कॉलोनी के हैं।

सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले मेडिकल कॉलेज में 140 एकांतवास बिस्तार थे। अब इनकी संख्या 510 कर दी गई है। 40 आइसीयू बेड व 14 वेंटिलेटर की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। अस्पताल में पहले से ही सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहां पर कोरोना संक्रमण जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। संसाधनों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो शहर के निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी। बेड कम पड़ेंगे तो दूसरे अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था भी है। सरकार ने प्रदेश में 11 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया है। प्रदेश के सभी जिलों को इन अस्पतालों में बांट दिया गया है। जिस जिले के लिए जो अस्पताल तय किया गया है, सभी कोरोना के मरीजों को उसी अस्पताल में रेफर किया जाएगा।

सड़क पर नोट गिराकर कोरोना की अफवाह फैला रहे लोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

बुध विहार में दो-दो हजार के नोट मिलने के बाद अब द्वारका में सड़क पर 500 रुपए के नोट पड़े मिले। कई दूसरे राज्यों में भी सड़कों पर पड़े नोटों को फैलाकर कोरोना से जोड़कर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने अफवाह उड़ाने वालों पर कार्रवाई की दी चेतावनी।

रोहिणी के पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा ने बताया कि पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग वायरस के खौफ में सड़क पर पड़े रुपए को भी उठाने में खौफजदा हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सड़कों पर पड़े नोट में कुछ शरारती तत्व कोरोना वायरस होने की अफवाह उड़ाकर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बीते तीन-चार दिनों से बढ़ गई है। वहीं नोट में कोरोना होने की अफवाहों पर विराम देने के लिए पुलिस भी हर भरसक प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी अफवाहों से लोगों को बचने की अपील की गई है। लोगों से अफवाह फैलने पर तत्काल मामले की सूचना पुलिस को देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि बुध विहार में दोपहर में दो दो हजार की करंसी मिलने की सूचना मिली थी। नोटों की संख्या सात थी। पुलिस अभी करंसी सील करने की योजना बना रही थी तभी एक व्यक्ति आ गए और बताया कि उन्हीं ने एटीएम से रुपए उठाए थे उसमें से सात नोट जेब से गिर गए थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद उन्हें रुपए सौंप दिए। उधर उपायुक्त द्वारका जिला एन्टो अल्फोंस ने बताया कि द्वारका सेक्टर-चार की सड़क पर एक पांच सौ रुपए का नोट पड़ा था।

खबरों में शहर

एमबीबीएस परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,10 अप्रैल।

गुरु तेगबहादुर अस्पताल से जुड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने एमबीबीएस पूरक परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने व बाल चिकित्सा विभाग की प्रायोगिक परीक्षाएं समय से कराने व नतीजे 30 अप्रैल से पहले निकालने की मांग की है। अस्पताल के आरडीए ने कालेज प्रशासन को लिखे पत्र में कहा है कि इससे मौलाना आजाद, लेडीहार्डिंग कॉलेज के बहुत से छात्रों के नीट या दूसरी पीजी प्रवेश परीक्षा में बैठने में सक्षम हो पाएंगे।आरडीए महासचिव डॉ सोनू ने कहा है तीनों कॉलेजों के 176 लोग एमबीबीएस की पूरक परीक्षाओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। एमसीआइ ने 30 अप्रैल तक इंटर्नशिप करने वालों को परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी है।

निगम स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने स्कूली छात्रों के लिए एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। पहले चरण के रूप में सभी वर्ग के शिक्षकों ने सभी वर्गों के लिए क्लास और सेक्शन आधारित वाट्सऐप बनाए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को पदोन्नति देने के निर्देश अगले 2-3 दिनों में दिए जाएंगे।

सूती कपड़े से बने तीन परत वाले मास्क बांटे गए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

गरीब, मजबूर, जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाते-बनाते कपड़ा निर्यातक तक का सफर तय करने वाली आस्था फाउंडेशन एवं सिनी डिजाइन की संस्थापक नीतू सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ा है। वे देशबंदी के दौरान फैक्टरी बंद होने के बाद भी गरीब, मजबूर, जरूरतमंदों का साथ दे रही हैं। फैक्टरी में रखे कपड़े से तीन लेयर मास्क बनवाने का प्रयास शुरू कराया है। मास्क तैयार कराकर 20 व 50 के पैकेट में डाल अस्पताल और घर-घर सामान पहुंचाने वालों को मुफ्त उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही घर के आस-पास बिना मास्क के घूमने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को मास्क बांट रही है।

परिवहन मंत्री ने किया अनाज मंडी का दौरा

फरीदाबाद, 10 अप्रैल (जनसत्ता)।

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ अनाजमंडी का दौरा कर गेहूं की खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना विषाणु से बचाव के लिए सभी आढ़ती सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। आगामी 20 अप्रैल से शुरू हो रहे खरीद सीजन के दौरान भीड़ से बचने के लिए बारी-बारी किसानों को अनाजमंडी में बुलाएं। परिवहन मंत्री ने आढ़तियों से बातचीत करते हुए कहा कि वे सामाजिक दूरी भी बनाकर रखें और बार-बार हाथ धोते रहें। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि पशु-पक्षियों का भी हम सब को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह बोल नहीं सकते हैं और गर्मी का मौसम है, इसलिए पशु-पक्षियों को खाना डालना और पानी पिलाने का प्रबंध करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने ऊंचा गांव की गौशाला का दौरा कर गौमाताओं को गुड़ खिलाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी आदेश पारित किए हुए हैं कि कोई भी मकान मालिक इस आपदा के समय किरायेदारों से किराया नहीं मांगेगा।

लोगों की शिकायत पर दुकानदारों की नई सूची जारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 अप्रैल।

संवेदनशील इलाकों के लिए दुकानदारों के मोबाइल नंबर की जारी की गई पहली सूची में लोगों की शिकायत के बाद बदलाव किया गया है। गलत नंबर हटाने समेत बाकी गलतियों का सुधार करते हुए नई सूची जारी की गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में घरों और सोसायटी तक सामान पहुंचाने वालों के नंबरों की नई सूची आरडब्लूए और गांव के लोगों तक पहुंचाई गई है। शनिवार से लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रवार को भी संवेदनशील इलाकों में रहने वालों के घर तक सामान पहुंचाया गया।

कोरोना की वजह से वाहनों का आवागमन बंद **परेशानी** शवों की अंत्येष्टि सीएनजी से करने की अपील की जा रही

देशबंदी : अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल पा रही लकड़ियां

आशीष दुबे
नोएडा, 10 अप्रैल।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण लागू हुई देशबंदी का असर अब अंतिम संस्कार पर पड़ने लगा है। देशबंदी के कारण पिछले करीब तीन सप्ताह से वाहनों का आवागमन बंद है। इस कारण नोएडा के सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवास में लकड़ियों की भारी कमी हो गई है। अंतिम निवास का संचालन कर रही संस्था नोएडा लोकमंच ने इस कमी के कारण अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों से लकड़ियों की जिद ना कर, बल्कि शवों का संस्कार सीएनजी से ही कराने की अपील की है। ताकि अंतिम निवास की व्यवस्था निर्विरोध चलती रहे।

नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशबंदी लागू की गई है। इस वजह से बुलंदशहर आदि इलाकों से पहुंचने वाली लकड़ियों की आवक रुक गई है। अब अंतिम निवास में संस्कार के लिए लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। ऐसे में सीएनजी से संस्कार किया जाना ही अपेक्षित है। लकड़ी की जगह सीएनजी से संस्कार किया जाना पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी उपयोगी है। साथ ही इसमें खर्च भी कम आता है। इसलिए लोगों से निवेदन किया है कि लकड़ी से संस्कार के लिए बाध्य ना करें और सीएनजी से ही संस्कार करवाएं।

सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवास में रोजाना करीब 15 शव और हर महीने औसतन 350 शव आते हैं। अभी तक इनमें से महज 10 फीसद शवों का सीएनजी के जरिए अंतिम संस्कार किया जाता है। लकड़ी के परंपरागत तरीके से संस्कार करने का 2500-3000 रुपए खर्च आता है, जबकि सीएनजी से यह 2000 रुपए आता है। गरीबों एवं लावारिस शवों का भी यहां निःशुल्क संस्कार भी किया जाता है। अंतिम निवास में सीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी आइजीएल से संस्था ने रियायती दर पर गैस की आपूर्ति करने की मांग की है। साथ ही जिलाधिकारी, सीईओ नोएडा से वन विभाग के डिपो से भी लकड़ियां उपलब्ध कराने को कहा है।

'कोरोना से जान गंवाने वाले शवों का किस तरह किया जाए संस्कार'

सेक्टर- 94 स्थित अंतिम निवास का संचालन कर रही संस्था नोएडा लोकमंच ने डीएम, सीएमओ, पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित शव के संस्कार के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने को कहा है। अगर ऐसे शवों का संस्कार किए जाने से पहले कर्मचारियों को कोई विशेष वर्दी, मास्क आदि पहनने अनिवार्य हैं, तो उन्हें भी यहां के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

पुलिस ने ई-पास और एंबुलेंस की व्यवस्था कर भेजा शव

भंगेल के रहने वाले एक युवक के पिता का बुधवार देर रात देहांत हो गया। युवक ने पिता के शव को गांव ले जाने के लिए नोएडा पुलिस को ट्वीट कर मदद मांगी। पुलिस ने ई-पास और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराकर उन्हें शव के साथ गांव भेजने की व्यवस्था कर दी। मूलरूप से बिहार के बेतिया जिला निवासी रवि तिवारी भंगेल में परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। उनके पिता शिव शंकर तिवारी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। रवि ने पिता को 3 अप्रैल को दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां बुधवार रात उनकी मौत हो गई। रवि ने तुरंत नोएडा पुलिस को ट्वीट कर शव को गांव ले जाने के लिए मदद मांगी। रवि के ट्वीट को संज्ञान में लेकर नोएडा पुलिस ने उससे संपर्क किया। इसके बाद पास और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें गांव भिजवा दिया।

www.readwhere.com

डब्लूएचओ ने जनस्वास्थ्य पर राजनीति को दी तरजीह

ताइवान की चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर भड़का अमेरिका

वाशिंगटन,10 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कोरोना को लेकर दी गई ताइवान की शुरुआती चेतावनियों को अनदेखा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) जनस्वास्थ्य पर राजनीति को तरजीह दी। ताइवान ने भी इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र निकाय प्रमुख की ओर से की गई आलोचना पर आक्रोश जाहिर किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक महामारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे डब्लूएचओ के वित्तपोषण को रोकने की धमकी देकर हमलावर हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की तरफ से डब्लूएचओ के खिलाफ अचानक दी जा रही धमकियां किसी विदेशी बली के बकरे को ढूंढने की राजनीतिक साजिश लगती है क्योंकि कोरोना को नियंत्रित करने व इस संबंध में ज्यादा प्रयास नहीं करने को लेकर फिलहाल ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डब्लूएचओ ने कोविड-19 को लेकर चेतावनी जारी करने में बहुत देर की और चीन का पक्ष लिया। मंत्रालय ने सवाल उठाया कि निकाय ने ताइवान की जानकारी का संज्ञान क्यों नहीं लिया। मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इस बात से बेहद परेशान है कि ताइवान की सूचना को वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय से क्यों छिपा कर रखा गया जैसा कि डब्लूएचओ के 14 जनवरी, 2020 के बयान में दिखता भी है कि उसने कहा था कि मानव से मानव में संक्रमण का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि डब्लूएचओ ने एक बार फिर जनस्वास्थ्य के बजाय राजनीति को चुना है। उसके इस कदम की वजह से 'समय और जिंदगी' दोनों बर्बाद हुईं।

ताइवानी राजनयिक शेन शिएन-जेन ने कहा कि चीन के निकट स्थित होने और करीबी संबंध होने के बावजूद ताइवान में वायरस के चलते केवल पांच मौत हुई। उसने 31 दिसंबर को ही मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण फैलने के बारे में डब्लूएचओ को आगाह किया है। महामारी विशेषज्ञ शेन ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' को बताया कि ताइवान के चिकित्सकों को पता चल गया था कि वुहान में उनके सहयोगी बीमार पड़ रहे हैं लेकिन डब्लूएचओ ने इस सूचना की पुष्टि करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

डब्लूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस ने बुधवार को एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि संकट शुरू होने के बाद से उनका कई बार अपमान किया जा चुका है। उन्होंने अमेरिका का नाम साफ तौर पर नहीं लिया लेकिन ताइवान का सीधे-सीधे नाम लिया। ताइवान ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए माफी की भी मांग की थी।

टेड्रोस के आलोचकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में डब्लूएचओ बेजिंग से ज्यादा करीबी दिखा रहा है और कोरोना वायरस को लेकर दी गई चीन की प्रतिक्रिया की प्रशंसा भी करता रहा है। लेकिन कुछ जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वुहान तक पहुंच बरकरार रखने के लिए डब्लूएचओ के पास कोई विकल्प भी नहीं है।

कोरोना : सुरक्षा परिषद की पहली बैठक

एकजुटता पर जोर

संयुक्त राष्ट्र, 10 अप्रैल (भाषा)।

दुनियाभर में कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई अपनी पहली बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही परिषद ने इस महामारी से निपटने के लिए महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रयासों के प्रति भी समर्थन जताया।

सुरक्षा परिषद ने कोरोना पर चर्चा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सत्र आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रमुख अंग की अध्यक्षता अभी डोमिनिकन गणराज्य के पास है।

गुतारेस ने भी सत्र को संबोधित किया। 15 देशों की सदस्यता वाले परिषद को संबोधित करते हुए, गुतारेस ने कहा कि 75 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से दुनिया अपने सबसे मुश्किल दौर में है और इस बात का डर है कि विशेष रूप से विकासशील देशों और पहले से ही संघर्ष से जूझ रहे देशों में अभी इस महामारी का सबसे बुरा प्रभाव सामने आना बाकी है।

महामारी से सामने आई कमजोरियां

संयुक्त राष्ट्र, 10 अप्रैल (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने कहा है कि कोविड- 19 महामारी ने इस बात का 'संकेत' दिया है कि विश्व में जैव-आतंकवादी हमले का परिणाम क्या हो सकता है। उन्होंने सचेत किया कि राज्येतर समूह उन 'खतरनाक विषाणुओं' तक पहुंच सकते हैं, जो विश्वभर में इसी प्रकार की तबाही मचा सकते हैं।

महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए इस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में पैदा हुए खतरों का जिक्र किया। परिषद ने डोमिनिकन गणराज्य की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए कोरोना संकट पर पहली बार विचार-विमर्श किया। गुतारेस ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष को 'एक पीढ़ी की लड़ाई' और इस तरह की समस्या से निपटने को संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य करार दिया।

गुतारेस ने कहा, ''कोविड-19 पहला और सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूरगामी हैं। यह महामारी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए बड़ा खतरा है। इससे सामाजिक अशांति और हिंसा बढ़ने की आशंका है जिससे इस बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता कमजोर होगी।' उन्होंने कहा, 'इस महामारी के कारण सामने आई कमजोरियां और तैयारी का अभाव इस बात का संकेत देता है कि एक जैव-आतंकवादी हमले के क्या परिणाम हो सकते हैं। राज्येतर समूह उन खतरनाक वायरस तक पहुंच हासिल कर सकते हैं जो विश्वभर में समाज को इसी तरह तबाह कर सकते है।'

आइसीयू से बाहर आए बोरिस जॉनसन

पिता ने कहा, बेटे को अभी आराम की जरूरत

लंदन, 10 अप्रैल (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लंदन के अस्पताल के गहन देखभाल कक्ष (आइसीयू) से बाहर सामान्य वार्ड में ले आया गया है। हालांकि वह अभी भी यहां के चिकित्सकों की करीबी निगरानी में हैं।

डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि सेंट थॉमस अस्पताल के वार्ड में भर्ती 55 वर्षीय जॉनसन का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं उनके पिता स्टेनली जॉनसन ने अपने बेटे को आराम करने की सलाह दी है।

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, 'प्रधानमंत्री आज शाम (गुरुवार) आइसीयू से वार्ड में आ गए हैं जहां ठीक होने के शुरुआती चरण में उनको करीबी निगरानी में रखा जाएगा। वे अच्छा महसूस कर रहे हैं।' स्टेनली जॉनसन ने कहा कि उनका पूरा परिवार 'बहुत आभारी' है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आइसीयू से बाहर आ गए हैं। साथ ही कहा कि उनका मानना है कि उनके बेटे की बीमारी ने 'पूरे देश को महसूस कराया कि यह गंभीर घटना है।'

उन्होंने बीबीसी से कहा, 'उन्हें आराम करना चाहिए...उन्होंने सभी के भले के लिए कठिनाइयां उठाईं और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे फूंक-फूंक कर कदम उठाए जाएं।' बोरिस जॉनसन की गर्भवती मंगेतर कैरी साइमंड्स ने जॉनसन के आईसीयू से बाहर आने पर ट्विटर पर राहत जताई है। कैरी खुद भी पृथक वास में रह रही हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते खुद में कोरोना के लक्षणों की जानकारी दी थी लेकिन उन्होंने कहा कि वह ठीक हो रही हैं।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या 7,978 हो गई है।

मंत्रियों और अधिकारियों ने ब्रिटेन की जनता से सामाजिक दूरी के सख्त नियमों का पालन करते रहने की अपील की है खासकर ईस्टर की छुट्टी के इस समय में जब यात्रा करना और देश के विभिन्न हिस्सों में दोस्तों एवं परिवारों से मिलना-जुलना एक परंपरा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा, 'पूरा देश अब से अगले तीन हफ्तों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के सख्त निर्देशों का पालन कर रहा है।'

सिंगापुर ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 'जूम' के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई

सिंगापुर, 10 अप्रैल (एपी)।

सिंगापुर ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 'जूम' के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ हैकरों ने जूम के इस्तेमाल के दौरान ऑनलाइन पाठ (लेसन) में सेंधमारी कर छात्रों को अश्लील तस्वीरें दिखाईं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सिंगापुर में आंशिक लॉकडाउन के तहत बुधवार को स्कूलों के बंद होने के बाद दो हैकरों ने भूगोल की ऑनलाइन कक्षा को बाधित किया।

स्कूलों के बंद होने के कारण शिक्षक ऑनलाइन तरीके से छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षक और छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम का इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हैकिंग की ये घटनाएं गंभीर हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है।

मंत्रालय के शिक्षा प्रौद्योगिकी खंड के निदेशक एरोन लोह ने बताया, 'सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए हम पहले से ही जूम के साथ काम कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर हमारे शिक्षक सुरक्षा संबंधी मुद्दे के समाधान तक जूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।' टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में व्यवधान से केवल सिंगापुर ही प्रभावित नहीं हुआ है। अमेरिका की संघीय जांच एजंसी एफबीआइ ने भी 30 मार्च को लोगों को आगाह किया था कि बैठक के लिए जूम का इस्तेमाल करने से बचे क्योंकि इस तरह की कई खबरें आई है कि हैकरों ने इस माध्यम में घुसपैठ करके अश्लील मैसेज या वीडियो प्रसारित किए।

चीन से वैश्विक पशु बाजारों को बंद करने की मांग

वाशिंगटन, 10 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिकी सांसदों के एक सर्वदलीय समूह ने चीन से कहा है कि वह अपने सभी पशु बाजार तत्काल बंद कर दें क्योंकि यहां से जानवरों से बीमारी इंसानों तक पहुंचने का बहुत बड़ा जोखिम है। वेट मार्केट कहे जाने वाले इन बाजारों में विभिन्न प्रकार के ताजा गोश्त के साथ स्तनपायी, सृप, मछलियां इत्यादि जिंदा बेची जाती हैं।

अमेरिका में चीन के राजदूत क्युई तिनाकाई को लिखे पत्र में सीनेटरों ने कहा, 'हम पत्र में चीन से यह अनुरोध करते हैं कि वेट बाजारों को तत्काल बंद करे क्योंकि इनसे पशुओं की बीमारियां (जूनोटिक डिसीज) इंसानी आबादी तक पहुंचने का जोखिम है।' उन्होंने कहा कि चीन के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक गाओ फू ने माना है कि नए कोरोना वायरस का स्रोत चीन के वुहान में सीफूड बाजार में अवैध तरीके से बेचे जा रहे जीव हैं। सीनेटरों ने कहा, 'दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि चीन के वेट बाजार दुनिया भर में सेहत संबंधी कई समस्याओं के स्रोत रहे हैं और उनका परिचालन तुरंत रोका जाना चाहिए ताकि चीनी जनता को और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अतिरिक्त स्वास्थ्य खतरों से बचाया जा सके।'

उन्होंने कहा, 'इसलिए हम चीन से इन सभी बाजारों को बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं जहां मनुष्य और वन्यजीव करीब आते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को बढ़ावा देते हैं।' इन 11 सीनेटरों के समूह में रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी, लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के क्रिस कून्स शामिल है। इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी ऐंड इन्फेक्शस डिसीज के निदेशक डॉ. एंथनी फॉसी ने इन बाजारों को बंद करने को कहा था।

यमन में कोरोना संक्रमण का पहला मामला

दुबई, 10 अप्रैल (एएफपी)।

यमन में सरकार के नियंत्रण वाले दक्षिणी प्रांत में शुक्रवार को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। कोविड-19 के लिए गठित शीर्ष राष्ट्रीय आपात समिति ने यह जानकारी दी। कई सहायता समूह पहले ही चेता चुके हैं कि युद्धग्रस्त यमन की लचर स्वास्थ्य प्रणाली के कारण वायरस का यहां पहुंचना घातक होगा।

समिति ने ट्वीट किया, 'हैड्राम प्रांत में कोरोना का पहला मामला सामने आया है।' उसने बताया कि संक्रमित व्यक्ति की हालत स्थिर है और उसका उपचार किया जा रहा है।

BNP PARIBAS MUTUAL FUND
Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972
Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. **Website:** www.bnpparibasmf.in • **Toll Free:** 1800 102 2595

NOTICE NO. 17/2020

Disclosure of Half Yearly Portfolio statement of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT in terms of Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regard from time to time, the Half Yearly Portfolio statement of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund as on March 31, 2020 has been hosted on the website of the Fund (https://www.bnpparibasmf.in/downloads/scheme-financials) and AMFI respectively.

Given the current situation due to Covid-19 pandemic, unit holders may request for a physical or electronic copy of the said Portfolio statement report **only** through telephone (call on Toll Free No. 1800 102 2595) or by email (customer.care@bnpparibasmf.in). Such copies shall be provided to the unit holders free of cost. However, unitholders are requested to note that there will be delays in providing the physical copies as it will be provided once the current situation normalizes.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited
(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)
Sd/-
Jyothi Krishnan
Head of Compliance, Legal & Secretarial
Date : April 10, 2020
Place : Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

YES MUTUAL FUND
YES Asset Management (India) Limited
602B, 6th Floor, Indiabulls Finance Centre (IFC) 1 & 2, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai – 400 013. **Website:** www.yesamc.in
Tel. No.: +91(22) 4082 7600 **Fax No.:** +91 (22) 4082 7653
Email: clientservice@yesamc.in **CIN** - U65990MH2017PLC294178

NOTICE NO. 30/2020

HOSTING OF HALF-YEARLY STATEMENT OF SCHEME(S) PORTFOLIO OF YES MUTUAL FUND ("YMF").

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92, dated June 5, 2018, the half-yearly statement of scheme(s) portfolio of YMF as on March 31, 2020, has been hosted on the website of YMF viz www.yesamc.in and AMFI viz www.amfiindia.com, respectively.

Unit holders may accordingly view/download the statements from the website of the YES Mutual Fund.

In the wake of the Covid-19 pandemic threat, resulting in a countrywide lockdown, and as a social-distancing measure to ensure the safety of investors, distributors, visitors and employees of YES Mutual Fund & its RTA, all Investor Service Centres/Branch Offices ("official points of acceptance") and Call Centres (Toll-free Number) of YES Mutual Fund have been closed until further notice.

Unit holders may submit a request for an electronic or physical copy of the half-yearly Portfolio Statement of the scheme(s) of YES Mutual Fund thereof, by writing to clientservice@yesamc.in. Please note that the requests for physical copies shall be serviced immediately after the lockdown is over.

Unit holders are urged to update their email ID and mobile numbers to help us serve them better.

For YES Asset Management (India) Limited
(Investment Manager for YES Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory
Place: Mumbai
Date: April 10, 2020

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

JM FINANCIAL MUTUAL FUND
JM FINANCIAL
NOTICE

Uploading half yearly portfolio for the period ended March 31, 2020 for the schemes of JM Financial Mutual Fund:

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the statement of portfolio of the schemes of JM Financial Mutual Fund ("the Fund") for the half year ended March 31, 2020 has been hosted on the website of the Fund viz www.jmfinancialmf.com and on the website of AMFI viz www.amfiindia.com.

The Portfolio/s of the respective scheme/s has/have been sent to all the investors whose email ids are registered with us. However, while the investors can refer to any of the above sites for the scheme's portfolio pertaining to their respective investments, they can also request for a physical/ soft copy thereof through any of the following means:

a) **Telephone:** Call our toll free number at 1800 1038 345
b) **E-Mail:** Send an email to investor@jmfl.com
c) **Letter:** Submit a letter at any of the Investor Service Centres of the Fund or Registrar M/s. KFin Technologies Pvt Ltd., details of which are available at www.jmfinancialmf.com.

Unit holders are requested to take note of the aforesaid.

Authorised Signatory
JM Financial Asset Management Limited
(Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)
Place : Mumbai
Date : April 10, 2020

For further details, please contact :
JM Financial Asset Management Limited
(Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.),
Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.
Corporate Office: Office B, 8th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025.
Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777
• Fax No.: (022) 6198 7704. • E-mail: investor@jmfl.com • Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
REF No. 02/2020-21

LIC MUTUAL FUND
LIC Mutual Fund Asset Management Limited
(Investment Managers to LIC Mutual Fund)
CIN No: U67190MH1994PLC077858
Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020
Tel. No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606
Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 03 of 2020-2021

NOTICE is hereby given that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the Half Yearly statement of schemes portfolio of LIC Mutual Fund ("LIC MF")for the Half year ended 31st March, 2020 has been hosted on the website of LIC MF viz. www.licmf.com and on the website of Association of Mutual Funds in India ("AMFI") viz. www.amfiindia.com.

Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of statement of schemes portfolio by any of the following modes:

1) Calling on toll free number: 1800-258-5678 from 9.00 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Saturday; or
2) Sending an email on service@licmf.com; or
3) Sending a written request to any of the Investor Service Centers of LIC MF nearest to the unitholders; or
4) Unitholders can SMS on +91 9250 333 444 for statement of scheme portfolios
   • SMS "HEPF" for electronic copy or SMS "PHPF" for physical copy from their registered mobile number.

Investors/Unit holders are requested to take note of the same.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED
Sd/-
Authorized Signatory
Date : 10/04/2020
Place: Mumbai

As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number with us to support paper-less communication.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND TARAKKI KAREIN!
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135
Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,
Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund
Half-Yearly Portfolio Statement of Schemes

NOTICE is hereby given that the half-yearly portfolio statement of schemes of ICICI Prudential Mutual Fund for half year ended March 31, 2020 has been hosted on April 10, 2020 on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018.

Investors may accordingly view/download the portfolio statement of schemes from the website of the AMC.

Investors can also request for the physical/soft copy of portfolio statement of schemes through any of the following modes:

1. Give a call at our Contact Centre at:
   • MTNL/BSNL: 1800 222 999
   • Others: 1800 200 6666
2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, details of which are available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

For **ICICI Prudential Asset Management Company Limited**
Sd/-
Authorised Signatory
Place : Mumbai
Date : April 10, 2020
No. 007/04/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ITI Asset Management Limited
Investment Manager for ITI Mutual Fund
Registered Office: Naman Midtown, 'A' Wing 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi Mumbai - 400013
Toll Free No: 1800 266 9603
B : 022 6621 4999 • F: 022 6621 4998
E : mfassist@itiorg.com
W : www.itimf.com
CIN: U67100MH2008PLC177677
ITI MUTUAL FUND
Long-term wealth creators

NOTICE No. 7/2020

Hosting of Half-yearly Portfolio Statement of the Scheme(s) of ITI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of the scheme(s) of ITI Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, ITI Asset Management Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Half Yearly Portfolio Statements of all the Schemes of ITI Mutual Fund for the period ended March 31, 2020 on its website viz www.itimf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com.

The Investors/Unitholders may accordingly view and download the Half Yearly Portfolio Statements from the website of the AMC and AMFI.

Unitholders can also submit a request for electronic or physical copy of the Half Yearly Portfolio Statement by writing to the AMC at the email address mfassist@itiorg.com or calling the AMC on the toll free number 18002669603 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of ITI Mutual Fund.

For ITI Asset Management Limited
(Investment Manager for ITI Mutual Fund)
Sd/-
George Heber Joseph
Chief Executive Officer & Chief Investment Officer
Place : Mumbai
Date : April 10, 2020

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

www.readwhere.com

गहराता संकट

अभी तक माना जा रहा था कि देशव्यापी बंदी का असर पड़ेगा और कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ेगी। पर पिछले एक हफ्ते में संक्रमितों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कोरोना पीड़ितों की तादाद तेजी से अब तेजी से बढ़ेगी। देश के तकरीबन सभी राज्यों से जिस तरह रोजाना नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है, वह चिंताजनक है। चौबीस घंटे में सबसे ज्यादा सत्तावन मामले तो राजस्थान में सामने आए हैं। इसके अलावा पंजाब के मोहाली में दस, जम्मू-कश्मीर में तेईस, उत्तर प्रदेश में इक्कीस, कर्नाटक में दस, हरियाणा में पांच मामले सामने आए हैं। जाहिर है, महामारी को फैलने से रोकने के उपाय ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सबसे पहले और ठोस के कदम के रूप में ही देशव्यापी बंदी जैसा फैसला किया। लेकिन पीड़ादायक बात यह है कि अभी भी तमाम राज्यों में लोग बंदी की अवहेलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की सख्ती के बावजूद मुंबई में सब्जी मंडी में भीड़ लगने के वीडियो रोज आ रहे है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ऐसा कई शहरों में देखने को मिल रहा है।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या छह हजार के ऊपर निकल चुकी है। रोजाना पांच सौ मामलों का औसत गंभीर बात है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे साफ है कि राज्य में हालात बेकाबू हैं। अकेले नाशिक जिले में बारह संक्रमित मिले। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में खतरा सबसे ज्यादा है। यहां लाखों लोग दयनीय हालात में रह रहे हैं और कोरोना से तीन लोग मर चुके हैं। संक्रमितों की संख्या भी बता रही है कि यहां सामुदायिक स्तर पर संक्रमण जैसी स्थिति बन गई है। कहने को राज्यों और केंद्र ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यह प्रयास बंदी को सख्ती से लागू कराने तक ही सीमित नजर आ रहा है। जिस व्यापक स्तर पर लोगों की जांच होनी चाहिए, वह नहीं हो रही। इसलिए भी संक्रमितों की संख्या अभी कम नजर आ रही है। अभी तक तकरीबन डेढ़ लाख लोगों की जांच हुई है। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने का खतरा ज्यादा इसलिए भी बढ़ा है कि पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात के कितने लोग देश भर में कहां-कहां गए और इस संक्रमण के वाहक बने, इसका अभी ठीक-ठीक अनुमान नहीं लग पाया है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि देश में अभी तक जितने भी मामले आए हैं, उनमें से एक भी जगह या शहर ऐसा नहीं है जहां तबलीगी जमात के लोग न गए हों और जितने मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें चालीस फीसद तबलीगी जमात के हैं।

भारत में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूर्ण बंदी पर सख्ती से अमल के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की जांच है। सारे शहरों में खासतौर से जहां ज्यादा कोरोना संदिग्ध हैं, लोगों की जांच का बड़े पैमाने पर अभियान चलना चाहिए। हालांकि भारत जैसे विशालकाय देश में यह काम जरा मुश्किल भरा है, लेकिन असंभव नहीं है। यह वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अभी एक बड़ा खतरा यह भी है कि बंदी के तत्काल बाद जिस तरह लाखों लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया, अगर उनमें संक्रमित लोग निकले तो यह महामारी ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार लेगी।

किसान की मुश्किल

पूर्ण बंदी के इस माहौल में कल-कारखाने, दुकानें, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, तो किसानों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कोरोना विषाणु का प्रकोप ऐसे समय में हुआ जब गन्ने, आलू, प्याज, दलहन वगैरह की फसलें खेतों में तैयार थीं और गेहूं की फसल तैयार हो रही थी। चीनी मिलें पेराई अवधि समाप्त होने से पहले ही बंद हो गईं, जिसके चलते गन्ने की बहुत सारी फसल अभी खेतों में खड़ी है। इससे गन्ना किसानों की परेशानियां समझी जा सकती हैं। अब गेहूं की फसल पक कर तैयार है, पर कटाई के लिए न तो पर्याप्त मजदूर मिल पा रहे हैं और न मशीनें। सामाजिक दूरी बना कर रहने और पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा न होने का नियम है, सो जहां स्थानीय मजदूर उपलब्ध हैं, वहां भी कटाई में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस साल थोड़े-थोड़े अंतराल पर मौसम का मिजाज भी बदलता देखा जा रहा है। बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में गेहूं की कटाई, मंड़ाई और फिर बाजार तक पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए किसान संगठनों की ओर से मांग उठ रही है कि सरकार इस मामले में कुछ दिलासे बरते और किसानों के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा करे, जैसे मजदूरों के लिए किया है।

दरअसल, खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक से दूसरे प्रदेशों में आवाजाही करते हैं। मसलन, कटाई के मौसम में बहुत सारे मजदूर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इसी तरह गेहूं की कटाई और मंड़ाई करने वाली बहुत सारी मशीनें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में जाती हैं। मगर पूर्ण बंदी की वजह से मजदूरों और मशीनों का आना-जाना भी बाधित हो गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने छूट दे दी है कि खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। इसी तरह मजदूरों पर से भी पाबंदी हटा ली गई है। यों खेती के काम में कभी वैसी भीड़भाड़ नहीं होती जैसी दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में देखी जाती है। सामाजिक दूरी के तय पैमाने जितनी दूरी वहां प्रायः रहती ही है, पर खेतिहर मजदूरों की आवाजाही खोलने से खेतों के अलावा दूसरी जगहों पर इसके पालन न हो पाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए पंजाब सरकार अगर यह छूट दे रही है, तो उसे इस पर मुस्तैदी से नजर रखने की जरूरत है।

किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त हैं। पर तैयार फसल की कटाई, मंड़ाई न हो पाए, उसे मंडी तक न पहुंचाया जा सके, तो यह दर्द असह्य हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो शहरों में दिहाड़ी करते थे या मनरेगा वगैरह में काम करते थे, वे गांवों में खाली बैठे हैं। उनकी मदद से कटाई-मंड़ाई का कुछ काम हो भी रहा है, पर पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर काम करने पर पाबंदी बाधा बन रही है। इतने कम लोगों से काम पूरा होना मुश्किल है। अब बंदी की अवधि में विस्तार होने के संकेत मिल चुके हैं, कोरोना संक्रमितों की पहचान और उनके उपचार की चुनौतियां बढ़ ही रही हैं। ऐसे में सरकारों को खाद्य उत्पादन का भंडारण और लोगों तक उसकी पहुंच सुगम बनाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा।

कल्पमेधा

जो गरीबों और दुर्बलों के पक्ष में बोलते हुए भयभीत होते हैं, वे दास हैं।

- लावेल

एकजुट होने का वक्त

प्रभात झा

जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने करोड़ों भारतीयों के हित में एक नहीं अनेक फैसले लिए। पर किसी कांग्रेसी या विरोधी दल ने स्वागत नहीं किया। क्या राष्ट्रीय संकट के इस समय में उन्हें सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए?

नियति की नीयत को कोई नहीं जानता। कोरोना विपदा के बारे में भी यही कहा जा सकता है। कोरोना वैश्विक महामारी है। सिर्फ भारत नहीं विश्व के लगभग 190 देश इसकी चपेट में है। उन देशों में भारत भी है जो कोरोना की वैश्विक आपदा से जूझ रहा है। यह संकट किसी के द्वारा लाया नहीं गया है, बल्कि स्वतः आया है। इसे ही प्रकृति प्रदत्त प्रकोप कहते हैं। आजादी के बाद भारत ने ऐसी किसी विकट विपदा का कभी सामना नहीं किया। इसे वैश्विक संकट में भारत की राष्ट्र के नाते बड़ी भूमिका हो गई है। कोरोना जन-जन का संकट बन चुका है। अच्छी बात यह है कि जन-जन के इस संकट से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का जन-जन अपने-अपने स्थान पर खड़ा हो गया है।

राष्ट्र जीवन में कभी-कभी ऐसा काल आता है, जब राष्ट्र के लिए सबको अपने-अपने विचारों को तिलांजलि देकर राष्ट्र ध्वज तिरंगे के सम्मान में और जनार्दन रूपी जनता के साथ होकर एक साथ खड़ा होना पड़ता है। यह समय ऐसा ही है। जिंदगी गरीब और अमीर हो सकती है, पर हर किसी की जिंदगी, जिंदगी होती है। एक अमीर की सांस का महत्त्व परिवार में जो होता है, उससे कहीं अधिक एक गरीब की सांस का महत्त्व उसके परिवार के लिए होता है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य है तो विचार करेंगे। विचार करेंगे तो तुलना भी होगी, आकलन भी होगा और समीक्षा भी करेंगे। पूरे देश की जनता राष्ट्र के संकट के दौरान सभी राजनीतिक दलों को पैनी निगाह की नजरों से देख रही है।

आज मैं जब तुलना करता हूं, तो मन में सहसा विचार आता है कि संगठन क्यों होता है? उसमें भी कार्यकर्ता आधारित संगठन का महत्त्व क्यों हो जाता है? एक कदम आगे जाएं, तो उस संगठन का महत्त्व और बढ़ जाता है जिसकी नीचे तक संगठनात्मक संरचना होती है। कहने को कांग्रेस सवा सौ साल से अधिक पुरानी पार्टी है। वर्षों तक भारत में उनका शासन रहा। पर दिक्कत यह रही कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को कभी भी परिवार से बाहर नहीं आने दिया। अतः धीरे-धीरे देश में उनकी संगठनात्मक संरचना समाप्त हो गई। कांग्रेस आज विरोध के लिए विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टी बन कर रह गई है। किसी भी दल में पार्टी से बड़ा नेता नहीं हो सकता। इसका ताजा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने हर संगठनात्मक भाषण में एक ही बात कहते है, 'नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है, यह तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश के प्रधानमंत्री पद पर लाकर खड़ा कर दिया।' क्या आज कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यह कहने की हिम्मत रखते हैं?

कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगाया और कोरोना के संकट को देखते हुए 24 मार्च आधी रात बजे से देश बंदी की घोषणा की। यह घोषणा देशहित में थी, न कि दल हित में। जब देश की बात आती है तो उसमें सभी दल, संस्थाएं व एक-एक नागरिक समर्पित हो जाता है। अटल जी कहा करते थे कि जब देश संकट में हो तो विचारधारा को चादर से ढक कर राष्ट्रधारा के साथ एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। भाजपा के लाखों कार्यकर्ता चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत अनुशासन और सामाजिक दूरी के साथ समाज के बीच जो काम कर रहे हैं, वह सदैव स्मरणीय रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि घड़ा-घंटी, शंख बजा कर, ताली बजा कर अपने-अपने घरों में उन सभी को सम्मान दें, जो अपनी जान जोखिम में डाल कर राष्ट्र में लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। भाजपा ने इस कार्यक्रम को अपनी संगठनात्मक व्यवस्थाओं के तहत शहर से लेकर गांव तक सफल बनाया, वहीं कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, जनता से अपील तक नहीं की।

जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने करोड़ों भारतीयों के हित में एक नहीं अनेक फैसले लिए। पर किसी कांग्रेसी या विरोधी दल ने स्वागत नहीं किया। क्या राष्ट्रीय संकट के इस समय में उन्हें सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या भारत सिर्फ भाजपा का राष्ट्र है? इस संकट में जन-जन की भावना की कद्र जो नहीं करेगा, उसे आने वाले

दिनों में जनता अच्छी तरह सबक सिखाएगी।

आज भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ऑडियो-वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत सक्रिय हैं। वहीं ऐसे समय में न कांग्रेस का 24, अकबर रोड सक्रिय है और उनके नेताओं के कार्यालय। उनके यहां से सिर्फ प्रधानमंत्री पर आरोप-प्रत्यारोप किया जा रहा है, न कि खुले रूप से आह्वान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय संकट में कांग्रेस हर कार्यकर्ता आपके साथ है। हम सोचते हैं कि कांग्रेस के नेता किस मुंह से यह बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई भी संगठनात्मक ढांचा नहीं है। हर कांग्रेसी यह कहता है कि कांग्रेस को हम नहीं जानते, जो भी है सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी।

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों सहित सभी प्रदेश अध्यक्षों से नित्य चर्चा कर रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों के जिला मंडल अध्यक्षों से चर्चा कर रहे हैं। संगठनात्मक आधार पर हर पदाधिकारी को देश में दस-दस जिले का दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक केंद्रीय मंत्री को देश के भिन्न-भिन्न राज्यों का कार्य सौंपा है। जहां सरकार कोरोना आपदा पर सूक्ष्म दृष्टि रखे हुए है, वहीं संगठन पूरी तरह अद्यतन जानकारी से युक्त रहता है। संगठन का महत्त्व इससे समझा जा सकता है।

आज हम जब नजर दौड़ाते हैं तो देखने में आता है कि परिवार आधारित राजनीति दलों के पास आज न विचार हैं, न कार्यकर्ता हैं और न संगठन है। अगर है तो सिर्फ परिवार के समर्थन और परिवार से लगाव रखने वाले लोगों का समूह। जब देश संकट से गुजर रहा हो और ऐसे में देश के सभी राजनीति दलों के कार्यकर्ताओं को स्वतः सक्रिय होना चाहिए और संगठनात्मक रूप से उतरना जाना चाहिए। भारत में जब पांच अप्रैल को प्रधानमंत्री ने रात नौ बजे नौ मिनट तक दीया जलाने का आह्वान किया तो देश में झुग्गियों में रहने वालों से लेकर अट्टालिकाओं में रहने वालों तक ने एक साथ खड़े होकर दीये जलाते हुए कोरोना से लड़ने का जन-जन में विश्वास जगाया। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया।

लोकतंत्र में दो पहिए होते हैं, एक सत्ता और दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष अपने सत्कार्यों से जन-जन में अपना स्थान बनाए रखना चाहता है और विपक्ष की भूमिका राष्ट्र प्रहरी के रूप में सत्ता निर्णय पर पैनी निगाह रखने की होती है। हम सब जानते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता के नाते न केवल भारत में, बल्कि जन-जन के मन में स्थान बनाया। उन्हीने कभी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं सोची, पर देश की जनता ने उनके बारे में अपना मन बनाया कि उन्हें आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आज देश में अटल जी और आडवाणी जी की तरह प्रतिपक्ष की जरूरत है जो राष्ट्रीय संकट में यह नहीं देखते थे कि केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है। वे सिर्फ यह देखते थे कि देश का हित किसमें है। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए विपक्ष भी कायम रहना चाहिए। काश! कांग्रेस सहित जो भी विपक्षी दल हैं, उन्हें भी यह समझ में आ जाए।

(लेखक राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

दूरदृष्टि की जरूरत

एकता कानूनगो बक्षी

आज की स्थिति तक पहुंचने और सभ्य समाज के निर्माण तक मनुष्य ने कई संकटों का सामना और कठिन संघर्ष किया है। मनुष्य का संघर्ष नया नहीं है। जब मनुष्य जंगल में रहता था तब नरभक्षी, हिंसक जानवरों और कई विषैली वनस्पतियों से उसे खतरा रहा होगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए उसे हर दिन कुछ नया सबक भी मिलता रहा होगा। वह कई नई अज्ञात बीमारियों की चपेट में भी आया होगा। कुछ लोग इन बीमारियों से दम तोड़ देते होंगे, कुछ बच जाते होंगे और फिर शुरू होती होगी संकटों से निपटने के उपाय तलाशने की कोशिशें, ताकि फिर से भीषण संकट न आ सके। निश्चित ही वह दौर 'प्यास लगने पर कुआं' खोदने जैसा रहा होगा। भूख और जायके की विविधता और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के अनुसार भोजन का आविष्कार हुआ होगा। हर दिन नया सबक, नया संघर्ष। आज जो बीमारियां हमारे लिए आम हैं, वे मनुष्य के प्रारंभिक दौर में और अधिक खतरनाक और असाध्य रही होंगी। यह क्रमशः मनुष्य के संघर्ष और विकास का परिणाम है कि हमने उन असाध्य व्याधियों पर नियंत्रण किया और उपचार के नए साधन खोज डाले और खुद को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया।

जरा सोचिए, उस समय भी मनुष्य कितना चिंतनशील रहा होगा। कितना सतर्क और सचेत रहता होगा। आज के दौर में जहां व्यवस्थित ज्ञान-विज्ञान के अलावा सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से पल भर में सूचनाओं और खबरों की बाढ़-सी आ जाती है, हमारे पूर्वज केवल अपनी सहज बुद्धि और विवेक से, खुद को सतर्क बनाए रख कर कितनी मुसीबतों का सामना करते रहे होंगे। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि 'देखो, समझो, करो और सीखो' युक्ति के तहत कितने ही प्रयोगों में कितनी ही बार वे लोग विफल हुए होंगे और कितनी ही बार स्वयं को खतरे में डाल दिया होगा। निश्चित ही वे अपनी इंद्रियों और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना बेहतर समझते थे।

दुनिया मेरे आगे

सोशल मीडिया पर आज हम जो चौबीसों घंटे कुछ कह रहे हैं, उसमें कई जानकारियों को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन लोग उन पर यकीन कर लेते हैं। हर व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ बिना जाने-समझे मैसेज को दूसरे के लिए आगे बढ़ा देता है। लगता है, हर कोई अब विशेषज्ञ बन गया है। कभी-कभी तो जरूरी और सही जानकारी और गलत जानकारी में अंतर ढूंढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम सब कहना चाहते हैं, सुनना, समझना और सीखना हम भूल चुके हैं। शायद बोलना, कहना सबसे आसान क्रिया है, और हम कितना सार्थक कह रहे हैं उसकी अब किसी को कोई परवाह नहीं है। जब हम अपना विवेक और आत्मचिंतन खो देते हैं, वहीं से गड़बड़ शुरू होने लगती है।

सामाजिक विकास के चरणों पर गौर करें तो निश्चित ही भोजन की महत्ता मनुष्य जीवन में सर्वोपरि रही है। उसके बाद अपनी सुरक्षा को लिया जा सकता है। इस संदर्भ में सामाजिक विकास के अनेक सिद्धांत आते रहे है, जिनमें अलग-अलग नजरिए से मनुष्य की मूलभूत जरूरतों, अभिलाषाओं और विलासिता आदि के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताया जाता रहा है। सबसे पहले हमारी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही अन्य अभिलाषाओं और विलासिता के बारे में सोचा जाए।

यह बिलकुल सामान्य समझ से पता चल जाता है कि हमारे आसपास के जीव-जंतु भी इस सिद्धांत को समझते है। पशु, पक्षी, जीव, जंतु तक अपना भोजन लेने से पहले पूरी सतर्कता से माहौल और संभावित खतरे को भांपते हैं। उसके बाद अपना भोजन ध्यान से लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच कर ही ग्रहण करते हैं। देखा जाए तो हम सभी की यही मूलभूत जरूरत है। भोजन, पानी, प्राणवायु, सुरक्षा, आवास यही सब हमारे अस्तित्व और जीवित रहने के लिए आवश्यक है।

बहरहाल, हम इंसानों के रोजमर्रा के जीवन की बात हो या देश और समाज-व्यवस्था की, मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के बाद ही दूसरे मुद्दों के बारे में सोचना और उनमें निवेश करना हर स्थिति में सदा प्राथमिकता में होना चाहिए। होता भी है, लेकिन यह भी सबक लेना चाहिए कि इस मामले में कभी-कभी कोई चूक बहुत तबाही का कारण भी बन सकती है। समाज और सरकारों को सदैव अपने चिंतन को विकसित और समीक्षित करते रहने की जरूरत है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वर्ग, विचारधारा और मतभिन्नता से ऊपर रहना जरूरी होगा।

बड़े बाजारों, गगनचुंबी इमारतों और शानो-शौकत दर्शाते निवेशों से कहीं पहले हमें जरूरत है हर व्यक्ति के लिए भोजन, स्वच्छ पानी, पर्यावरण, सस्ते आवास, शारीरिक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, आधुनिक सर्वसुलभ अस्पताल, बेहतरीन और सस्ते स्कूल, सुरक्षित यातायात साधनों और सुविधाओं की। आज वह समय नहीं रहा जब प्यास लगने पर कुआं खोदा जा सके। अब हम पहले से अधिक विकसित और संपन्न होने के साथ प्रबुद्ध समाज का हिस्सा है। दूरदृष्टि हमारे व्यवहार और मानस में सबसे आगे हर बार दिखाई देनी चाहिए।

संकट का कारण

भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। सभी विकसित देश इस वायरस से पूरी तरह से दहशत में आ चुके हैं और हाथ खड़े कर चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पांच हजार से ऊपर निकल गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी डेढ़ सौ से ज्यादा हो गया है। पूरा देश बंद है। काम ठप हैं, इससे दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को काफी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद के अतरिक्त कोई उपाय नहीं है। सामाजिक दूरी ही इसका रामबाण इलाज है। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी पूरी तरह से लोगों की जान बचाने में जुटे हैं।

फिलहाल लोगों का पहला कर्तव्य यह है कि वे बंदी के नियमों का सख्ती से पालन करें और सरकारी काम में बाधा न बनें। जिस प्रकार से तबलीगी जमात के बड़ी संख्या में लोग चुपचाप देश के अन्य हिस्सों में आते जाते रहे, उससे महामारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो यह रहा है कि पुलिस जब तबलीगी लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है तो उस पर हमले किए जा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों व दूसरे कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घटनाएं चिंता का कारण बन गई हैं। जहां एक ओर पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है और इस महामारी से लड़ रहा है, वहीं कुछ लोग संकट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में भी इटली, अमेरिका जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी।

● *नीतीश कुमार पाठक, औरंगाबाद (बिहार)*

सीखने का वक्त

मानव समाज की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में कोरोना ने जिस तरह आम जनजीवन को ठप कर दिया है, ऐसी स्थिति में भी लोग यदि मानवीय संबंधों के प्रति संवेदना उत्पन्न करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव जाति का और कुछ नहीं होगा। इस प्रकृति के छोटे-बड़े असंख्य तत्वों के साथ-साथ मानव भी एक छोटा-सा प्राणी है। मानव ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर किया, जिससे लगा कि इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसने प्रकृति पर विजय पा ली है। लेकिन ऐसा सोचना मानव समुदाय के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाने वाला अमेरिका भी आज कोरोना से हिल गया है।

पर दूसरा पक्ष भी देखें। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण से काफी हद तक मुक्ति मिली है। वायु शुद्ध हो गई है, नदियों का पानी निर्मल होता जा रहा है, पंछियों की चहचहाहट सुनाई पड़ने लगी है। यह वक्त हमें कुछ सिखा रहा है और संदेश भी दे रहा है, यह कि अब हमें संभल जाना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर देना चाहिए।

● *मिथिलेश कुमार, बलुआचक (भागलपुर)*

बनना होगा जिम्मेदार

कोरोना से जंग में कामयाब होने के लिए हम सभी एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस कामयाबी के लिए बिना किसी अवरोध के सभी का सहयोग अपेक्षित है। देशव्यापी बंदी के इतने दिनों बाद आज सभी भी कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो सहयोग प्रशासन को चाहिए, वह नहीं मिल रहा है! ऐसे में कोरोना से मुक्ति की पूर्ण कामयाबी जल्दी से जल्दी कैसे मिलेगी, यह प्रश्न उन लोगों के समक्ष है, जो बंदी का न तो पालन करते हैं और पालन कराने वाले सुरक्षाकर्मियों पर हमला करते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाते हैं। जांच करने वाले को सही जानकारी देने की बजाय अपमानित करते हैं, कई लोग जांच कराने की बजाय छिपे फिरते हैं। ऐसे में हम जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त होने के लिए कैसे कामयाब होंगे? सहयोग ही कामयाब होने की मूलभूत बुनियाद है, इसे समझना होगा।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

झूठी खबरों से बचें

एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चलने वाली झूठी खबरों ने भी समस्या पैदा कर दी है। ऐसी सूचनाएं और खबरें देख कर लोगों में हड़कंप और डर मच जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर लें।

● *नौमान किदवई, लखनऊ*

धार्मिक ठिकाने भी दें मदद

कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी देशों में चिंता है। लगभग सभी देश व्यापार के मामले में एक-दूसरे से लगभग कट चुके हैं। अभी यह बुरा दौर कितने दिन चलेगा, इसका अंदाजा शायद कोई भी नहीं लगा सकता। कोरोना ने कहर बरपा कर लोगों के जीवन को तो खतरे में डाला ही है, देशों की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर डाला है। लेकिन फिर भी इस आर्थिक संकट से देश को उभारने के लिए सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों को अपनी जमा धन-दौलत को संकट के हवाले करना चाहिए, ताकि सरकार इससे देश के कल्याण और कोविड-19 के इलाज पर खर्च कर सके।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

जांच का दायरा

देश में कोरोना के मामले रोजाना रहे हैं। फिलहाल तो सरकार बंदी करके स्थिति को संभालने में लगी है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? भारत में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा जोरशोर से हो रही है, जो काफी हद तक सही रणनीति का परिणाम है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अब कोरोना नियंत्रण में है। लंबी कवायद, जांच और लोगों के सहयोग से इसे काबू कर लिया गया है। समस्या यह है कि भारत में कोरोना की जांच का काम अभी तक कछुए की चाल से चल रहा है। जब तक सरकार जांच का दायरा नहीं बढ़ाती, तब तक पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत में कोरोना कब थमेगा।

● *दीपक कुमार, कोटपूतली (राजस्थान)*

www.readwhere.com

शुक्र है

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर शुरू में नौकरशाही ने लचर रवैया अपनाया था। नतीजतन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक ही था। भृकुटि तनी तो नौकरशही को संकट का वास्ता दे कर्तव्यनिष्ठा की घुट्टी पिलाई। सूबे के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने फौरन तेवर दिखाए। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को खुद सामने न आने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। जमाती सामने आने लगे और पुलिस ने लाकडाउन का भी कड़ाई से पालन कराया। लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलती रहें, यह प्रबंधन भी कुशलता से हुआ। हरिद्वार ठहरा धार्मिक आस्था का शहर। हर की पैड़ी पर देश भर से श्रद्धालु डुबकी लगाने और अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। इन रस्मों और रीति रिवाजों को रोकना पड़ा है। फिलहाल तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव नितेश झा, डीजीपी अनिल रतूड़ी और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की टीम कोरोना संक्रमितों की पहचान और इसका फैलाव रोकने के मिशन में जुनून के साथ जुटी है। गनीमत है कि अभी तक सामने आए संक्रमित महज 35 हैं। शुक्र है कि एक भी पीड़ित की जान नहीं गई है अभी तक इस पर्वतीय सूबे में। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री के साथ वीडिया कांफ्रेंसिंग में खासा सबल नजर आया।

बेबाक बोल

कोरोना विषाणु ने जब दवा और दुआ दोनों को अशक्त साबित कर दिया, धर्म और विज्ञान के पास भी सामाजिक अलगाव के सिवाय कोई हल नहीं था तब भी अमेरिका को यही चिंता थी कि उसके मुनाफे में कोई कमी नहीं आए और वैश्विक संबंधों पर उसकी धौंस कायम रहे। पहले तो कोरोना विषाणु के संक्रमण पर घोर लापरवाही बरती और बाद में हालात बेकाबू हो जाने के बाद दूसरे देशों के वेंटिलेटर से लेकर मास्क तक पर कब्जे की बदनीयती दिखाई। मलेरिया की दवा पर भारत के दोस्ताने रुख के बावजूद अमेरिका के अगुआ ने पहले जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, वह नई नहीं है। कोरोना पर ट्रंप की भाषा से लगता है कि मानो अमेरिका को बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। एकध्रुवीय वैश्विक संबंध पर एक बार फिर सवाल उठाता बेबाक बोल।

कुनैन कथा

मुकेश भारद्वाज

'लोग समझे अपनी सच्चाई की खातिर जान दी
वर्ना हम तो जुर्म का इकरार करने आए थे'

नंगी आंखों से नहीं दिखने वाले कोरोना विषाणु ने पूरे विश्व की व्यवस्था को नंगा कर दिया है। अभी तक हम कोरोना को लेकर अमेरिका की असहाय स्थिति की बात कर रहे थे और आज जेरे बहस में है उसकी आक्रामकता। बजरिए अमेरिकी लोकतंत्र डोनाल्ड ट्रंप का शासन पूरे विश्व में नवउदारवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए पुनर्पाठ सा है। इस महाशक्ति पर आरोप लगता है कि उसने एक कमजोर देश के लिए भेजे जा रहे वेंटिलेटर पर कब्जा कर लिया। कनाडा, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक ने आरोप लगाए कि अमेरिका मास्क जैसी चीजों पर गंदी राजनीति कर रहा है। विषाणु का खतरा जब पूरे ग्लोब पर है तो इसका स्वयंभू सरपंच कहता है, सबसे पहले मैं और मेरा अमेरिका।

राजनीतिक विद्वानों का कहना रहा है कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का अंतर संकट के समय ही सामने आता है। अमेजन के जंगल में लगी आग हो या जलवायु परिवर्तन का संकट, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा एक अहंकारी अधिनायकवादी की ही रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग से वो जिस तरह उलझे वह समसामयिक इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। आज कोरोना विषाणु को लेकर अमेरिका और चीन से लेकर क्यूबा तक का मॉडल हमारे सामने है। अगर इन तीनों का फर्क अभी तक समझ नहीं आ रहा था तो मलेरिया की दवा से निकली बहस को ही समझ लें।

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन मांगते हैं और उन्हें सकारात्मक जवाब मिलता है। मतलब उनकी मांग उन तक पहुंचनी थी। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने कहा कि वो खुद इस दवा की गोली लेना चाहेंगे, अगर उनके चिकित्सक अनुमति देंगे। अमेरिका वह देश है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18 फीसद तक खर्च करता है। वहां की प्रयोगशालाओं में दवाओं को लेकर अंधाधुंध प्रयोग होते रहते हैं, जहां से हर मर्ज का पेटेंट के साथ इलाज निकलता है। पेटेंट यानी कि सार्वजनिक हित की चीज पर खास वर्ग के हित का पट्टा मिल जाना, उसके उत्पादन से लेकर वितरण तक पर आर्थिक हित का लगाम अपने हाथ में पकड़े रहना। कोरोना काल में अमीर देशों से ही खबरें आईं कि पेटेंट के शिकंजे के कारण चाह कर भी सस्ता इलाज नहीं दिया जा सका। अमेरिका में ही पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई।

अब कुनैन की गोली पर किचकिच को किस संदर्भ में देखें। पूरे परिदृश्य में मलेरिया की दवा को इतना उछाल मिलने के बाद उस कंपनी के स्वामित्व और मुनाफे की कुंडली भी खंगाली गई जो इसे बनाती है। जब ट्रंप के दावे और भारत के इस दवा पर से निर्यात की पाबंदी हटाने की तारीख पर बहस चल रही थी तो भारत श्रीलंका के लिए इस दवाई की खेप जारी कर चुका था जहां इसकी बहुत जरूरत थी। ब्राजील के राष्ट्रपति दवा भेजने के

लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह चुके हैं। हालांकि दवा के लिए धन्यवाद ज्ञापन ट्रंप की ओर से भी आ चुका है।

तो कुनैन की गोली के जरिए ट्रंप का मकसद था अमेरिका का अमेरिका की तरह दिखना। ट्रंप को अपनी भाषा में युद्धोन्माद से लेकर राष्ट्रवाद को लाना था और वो ऐसा करते रहे हैं। हम लोकतंत्र और साम्राज्यवादी सुर में अंतर करने की जिस अवधारणा की बात करते हैं यह उसका प्रयोगात्मक रूप है।

अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डूबने लगता है तो वो कमजोर देश के तिनके का सहारा लेता है। लेकिन उसकी नजर उस तिनके पर ही आधिपत्य की हो जाती है कि अब किसी कमजोर को भी मिले तो मेरे हिस्से के मुनाफे के साथ। उस पर मुहर मेरे वर्चस्व की रहे। अमेरिका के लोगों को लगना चाहिए कि उनका अगुआ उन्हें बचा सकता है। वह मसीहाई अंदाज में कहते हैं कि मलेरिया के इलाज की यह गोली मैं भी ले सकता हूं। नागरिकों की चिंता के नाम पर किए संबोधन में अपने मजबूत शासकीय चेहरे को बचाने की चिंता साफ झलकती है।

अब दूसरी ओर हम चीन के मॉडल को देखते हैं। चीन भी नवउदारवादी ढांचे में ही ढला हुआ देश है। लेकिन कोरोना काल में उसकी रणनीति रही कि पहले खुद बचेंगे फिर दूसरों को बचाएंगे। उसकी यह भी चिंता थी कि उसके बचने के लिए वैश्विक बाजार का बचना जरूरी है। बाजार रहेगा तभी उसका माल बिकेगा। सबसे पहले वो अपने ढांचे को बचाने के लिए जुटता है। सर्विलांस और तकनीक का सहारा ले जनवादी अधिकारों को बंधक बना कोरोना विषाणु के गढ़ को संक्रमण मुक्त करता है। वह इस तबाही के मंजर पर हाथ नहीं सेंकता है। खुद को बचाता है, बाजार को बचाने की कोशिश करता है और दूसरे देशों की मदद में जुट जाता है। अब जब वुहान में तालाबंदी खुल चुकी है और शहर में जीवन पटरी पर लौट रहा है तो अमेरिका के अगुआ से लेकर अन्य अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे आधिकारिक भाषा में कोरोना को वुहान विषाणु या चीनी वायरस नहीं कहेंगे।

कोरोना संक्रमण के भारत में फैलने और हालात बिगड़ने के बाद से हम इस स्तंभ में इसी सवाल से जूझ रहे हैं कि इस वैश्विक विषाणु से थमने के बाद ग्लोब के चलने का इंजन क्या होगा। वैश्विक बाजार पर अपने एकाधिकार के लिए युद्धोन्माद की भाषा बोलते रहने वाला अमेरिका कभी वेंटिलेटर पर धमकाता है तो कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया जाने वाला अपना अनुदान रोकने का एलान करता है।

कोरोना विषाणु से जूझ रहे विश्व में अमेरिका की धमकी, स्वार्थ और तंज की भाषा नया राजनीतिक कथ्य गढ़ रही है। ट्रंप बता रहे हैं कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। और, अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जाने का मतलब है दूसरे देश के नागरिकों के लिए भेजे जा रहे वेंटिलेटर और मास्क को हड़पने की कोशिश करना। इतने बड़े संकट में भी अमेरिका ने उन देशों से आर्थिक पाबंदी नहीं हटाई जो अपनी तबाह अर्थव्यवस्था में भी कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया की मदद का जज्बा दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि हमने बम और मिसाइल नहीं, डॉक्टर तैयार किए हैं।

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बार-बार यह सवाल उठा रही है कि अब हमारा वैश्विक रुख क्या होगा। अमेरिका का रवैया तो ऐसा है कि मानो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है उसे बचाना, लेकिन दुनिया को लेकर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित चीन से पुराने रिश्ते को याद कर नए तरीके से विश्लेषण हो रहा है। अमेरिका एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जो पूरे वैश्विक संबंधों को चुनौती देता रहा है। एकध्रुवीय शक्ति संबंध का बोझ क्या यह दुनिया आगे उठा पाएगी? जनवरी से लेकर अब तक चीन को लेकर अमेरिका की भाषा का विश्लेषण किया जा चुका है।

अमेरिका में हालात भयावह हैं, लेकिन उसके अगुआ की भाषा 'मेरा भय कायम रहे' वाली है। चीन तेजी से उबर कर दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा चुका है। आगे की बात करें तो चीन के पास रसायन निर्माण के कारखाने हैं तो भारत के पास उन रसायनों के मिश्रण से दवा बनाने की अद्भुत क्षमता। मौत के मंजर पर भी अमेरिका मुनाफे की मुनादी का शोर मचाता रहा और धौंस दिखाता रहा। सवाल यही है कि कोरोना संकट से निकलने के बाद नया विश्व किस व्यवस्था की ओर उम्मीद से देखे? कोरोना के बाद उभरे एकध्रुवीय विश्व के संकट पर यह बहस जारी रहेगी।

राजपाट

वन मैन आर्मी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कोरोना कम मुसीबत लेकर नहीं आया। अपने मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं कर पाए बेचारे। कमलनाथ सरकार के त्यागपत्र के बाद चौहान ने 23 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली थी। इससे एक दिन पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री की अपील पर देशभर में जनता कर्फ्यू था। चौहान ने जल्दबाजी में अकेले ही शपथ ली थी। मंत्रिपरिषद का चयन करने का वक्त ही नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों से किए गए वादों पर भी तो खरा उतरना था। चर्चा तो यहां तक थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों में से एक को उपमुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। इसी कुर्सी की हसरत भाजपा के नरोत्तम मिश्र की भी होगी ही। आखिर दल बदलुओं के समर्थन से कर्नाटक में बनी भाजपा सरकार में भी तो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ एक-दो नहीं बल्कि तीन उपमुख्यमंत्री हैं। बहरहाल कोरोना से जारी जंग से बतौर सरकार अब मुख्यमंत्री शिवराज चौहान अकेले ही लड़ रहे हैं। मंत्रियों का चयन एक तो कैसे ही उनके लिए हंसी खेल नहीं है। ऊपर से आलाकमान की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ने वालों की फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। पर उनके चक्कर में अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। पाठकों को बता दें कि मुख्यमंत्री इकलौते सरकार तो जरूर चला सकते हैं पर कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते। कैबिनेट तभी मानी जाती है जब मुख्यमंत्री के अलावा कम से कम एक मंत्री तो जरूर हो। फिलहाल उन्हें सारे फैसले कैबिनेट से अनुमोदन की प्रत्याशा में करने पड़ रहे हैं। चौहान अकेले नहीं हैं। ऐसी ही परिस्थिति से येदियुरप्पा को भी जूझना पड़ा था। जिन्होंने कुमार स्वामी सरकार के पतन के बाद खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ तो पिछले साल 26 जुलाई को अवश्य ले ली थी पर मंत्रिमंडल का गठन एक महीने बाद कर पाए थे। इस दौरान शिवराज चौहान की तरह ही अपने सूबे में वे भी 'वन मैन आर्मी' रहे।

नायाब मिसाल

कोरोना विषाणु के वैश्विक प्रकोप और उसके कारण 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में जारी तीन हफ्ते की लॉकडाउन अवधि में राजस्थान सरकार ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी धाक जमाई। पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका श्रेय खुद लेने के बजाए दिन-रात जूझ रहे कोरोना योद्धाओं को ही दिया। सूबे के औद्योगिक शहर भीलवाड़ा का उदाहरण सारे देश की नौकरशाही के लिए अनुकरणीय हो गया है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट तो एक भी दिन चैन की नींद नहीं सोए। कमाल तो यह है कि भट्ट सीधे आइएएस सेवा में नहीं आए। राजस्थान राज्य सिविल सेवा से तरक्की पाकर आइएएस बने हैं। कलेक्टर का पद आइएएस के लिए है। मातहतों से उत्तम तालमेल बनाया उन्होंने। उनकी चौकसी, मेहनत और कुशलता ने भीलवाड़ा को बचा लिया तभी तो देश के कैबिनेट सचिव ने भी सराहना की उनकी। दूसरे कलेक्टरों को भीलवाड़ा माडल अपनाने की सलाह भी दे डाली। स्वास्थ्य महकमे को देख रहे वरिष्ठ आइएएस रोहित कुमार सिंह ने भी दूरदृष्टि से काम लिया और सूबे में कोरोना का संक्रमण बेकाबू नहीं होने दिया। टीम भावना से काम करने के लिए शोहरत है उनकी। पहले केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय में रहते हुए भी यश कमाया था। मुख्य सचिव से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक शासन-प्रशासन का पूरा तंत्र राजस्थान में समन्वय के साथ कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में हुए कोरोना के विस्फोट ने अलबत्ता राज्य सरकार को परेशान कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस इलाके के लिए अलग से एक आइएएस को नोडल अफसर बना दिया। सरकार को विश्वास है कि भीलवाड़ा की तरह रामगंज से भी निपट लेगी। अशोक गहलोत कर्मठ अफसरों के पारखी माने जाते हैं। उनका प्रोत्साहन मिलने से नौकरशाह गुटबाजी भुलाकर मिशन भाव से जुटे हैं।

नई डगर

जन धन की हानि और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को तो कोरोना के संदर्भ में हर कोई चर्चा कर रहा है। पर सियासत और सियासी दिग्गजों को होने वाले इसके नुकसान का आकलन करने की अभी हमें फुर्सत ही नहीं। बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही लें। भाजपा में कौन-कौन से मंसूबे लेकर शामिल हुए थे। केंद्र सरकार में बरास्ता राज्यसभा मंत्री बन गए होते अब तक तो। उनके समर्थक पूर्व विधायकों का भी पुनर्वास हो चुका होता। पर कोरोना ने व्यवधान डाल दिया। कोरोना के कारण चुनाव आयोग को राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव भी टालने पड़ गए। पर दिल की धड़कन तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछो कितनी बढ़ गई थी। पिछले साल 28 नवंबर को ली थी उद्धव ने शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन के नेता के नाते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनका बेटा आदित्य ठाकरे मंत्री है उनकी सरकार में। उद्धव की दुविधा यह है कि वे विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं अभी तक। इस रूप में अधिकतम छह महीने ही रह सकते हैं मुख्यमंत्री। योजना तो निर्वाचन के जरिए विधान परिषद सदस्य बन जाने की थी पर कोरोना के कारण कौन जाने कब करा पाएगा चुनाव आयोग यह चुनाव। लिहाजा नई तरकीब सोच ली। गुरुवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नामित करने की सिफारिश कर दी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। पाठकों को बता दें कि सरकार की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद में समाज के दो नामचीन लोगों को नामित कर सकते हैं राज्यपाल। दोनों सीटें खाली भी पड़ी हैं। जिस बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने की। मामला उद्धव के हित से जुड़ा था तो इस बैठक से खुद को अलग रख ठीक ही किया उन्होंने। हो सकता है कोश्यारी इस सिफारिश पर तत्काल कोई फैसला न लें पर नियमानुसार तो वे मंत्रिपरिषद की सलाह को ठुकरा नहीं पाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी मिली तो नया सियासी इतिहास बनेगा एक नामित सदस्य के मुख्यमंत्री बनने का। निर्दलीय विधायक के नाते किसी सूबे का मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड तो खैर पहले ही झारखंड में मधु कोड़ा के नाम दर्ज है।

प्रस्तुति : अनिल बंसल

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

खूफिया तंत्र की तंद्रा

मरकज-ए-मरघट के चित्रण से स्पष्ट है कि कोरोना के विषाणु से अधिक खतरनाक मानव मस्तिष्क से उपजे वे हालात हैं जिसने चुनौती की गहराई और बढ़ा दी है। डर यही है कि जिस खुफिया तंत्रों की तंद्रा ने पुलवामा के बाद मरकज होने दिया। भविष्य में इन दोनों घटनाओं की तीव्रता से आच्छादित कोई अन्य भयंकर विपदा देश के सामने न ला दे। फिर हर बार की तरह हमारा तंत्र सांप के निकल भागने के बाद लाठी पटकते नजर आएगा। चीनी विषाणु आपदा ने अपने विकृत रूप से विश्व को रूबरू कराते हुए बता दिया है कि किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का चरित्र क्या हो सकता है। यह त्रासदी गुजर जाएगी। बाद में इसके निशान जो रह जाएंगे वे साक्षी होकर अपनी पटकथा लिख सकेंगे कि इस आपात में कौन, कैसे निपट सका। तब तक संभवत: यह भ्रम और क्रम छिन्नभिन्न हो जाए कि संसार में सबसे शक्तिशाली देश कौन है। निजामुद्दीन मरकज का घटनाक्रम केवल रोग का उजागर होना नहीं था बल्कि धर्मांधता का वह सैलाब रहा जिसने पूरे मुल्क को अपने आगोश में लेकर मानवतावादी मूल्यों को तार तार कर दिया।

मरकज से जिस व्यापकता से संक्रमण बढ़ा वह चिंताजनक तो है ही लेकिन बुनियादी सवाल यह भी है कि शरीर पर हमला करने वाले विषाणु का इलाज तो संभव है, लेकिन ऐसी लापरवाही करने वालों का इलाज कब होगा। कोरोनो विषाणु से उबरने के बाद नैतिक और अनैतिक की जंग होगी जिसमें चीन दमदार तो होगा लेकिन अपने घटते-गिरते साख की कसौटी पर ही। इस भयावह काल में भारत एक आशा बनकर उभर सकता है समय का तकाजा है कि मिलकर हमसब दुआ करें कि यह कोरोना का विषाणु जल्दी ही खत्म हो।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना ।

भारत दे रहा एकता का संदेश

किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ताधारी दल से ज्यादा वहां के विपक्षी दल का मजबूत होना 'स्वच्छ लोकतंत्र' की निशानी है। यह बात विकसित व विकासशील दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि मजबूत विपक्ष वह आइने के समान होता है जिसमें लोकतंत्र का चेहरा साफ-साफ नजर आता है। उदाहरण के लिए भारत को लेकर देखें तो पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने आतंकियों, भ्रष्टाचार और मजबूत लोकतंत्र की परिकल्पना को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक ओर पूरी दुनिया के तकरीबन दो सौ देश कोरोना महामारी की ताबाही झेल रहे हैं।

तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आम जनता अलग-अलग माध्यम से ताली-थाली और दीप जलाकर एकता का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। भारतीय लोग अपनी पौराणिक संस्कृति के माध्यम से किसी भी नकारात्मक शक्ति या बिमारी को सामाजिक अलगाव से मात देने का भरतपूर प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद भी है कि हम भारतीय जल्द ही कोरोना विषाणु को हराकर विजयी हो पाएंगे।

-नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

असहाय व्यवस्था

जबसे नए विषाणु का आगमन हुआ है दुनिया में परहेज से इलाज तक नए-नए नुस्खे इजाद हो रहे हैं। कहते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने में आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता मददगार होती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में वह ताकत हो या न हो मगर देश की व्यवस्था काफी कमजोर और असहाय दिख रही है। हिंदुस्तान की देशबंदी निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया गया फैसला है। मगर बेरोजगार हुए लाखों प्रवासी परिवार जब हाईवे पर आ गए तो प्रशासन के तो हांथ-पांव फूल गए। समझ न आया कि हांथ धुलाएं, दूरी बनाएं या भोजन कराएं। आज वह भीड़ कहां है, किस हाल में है, किसने किसको बीमार किया? न कोई खबर न कोई शोर न हंगामा। वैष्णों देवी की यात्रा पर गए लाखों तीर्थयात्रियों की अधूरी यात्रा किस हाल में है, कोई क्यों नहीं बताता? भीड़ वहां भी है और कोरोना की पंहुच भी, तो उनकी फिक्र किसी को क्यों नहीं है? देशी खुफियातंत्र अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहा है जिसने मरकज की उस जमात को ढूंढ़ निकाला। सवाल यह है कि जानते हुए भी कि एक भी बीमार किसी भीड़ को शोलों में तब्दील कर सकता है, मरकज की निगहबानी में चूक कैसे हुई? तबलीगी जमात की जहालत पर सवाल उठा कर हमारा सरकारी अमला इस इल्जाम से बरी नहीं हो सकता है।

-एमके मिश्रा, रातू, रांची (झारखंड) 835222।

www.readwhere.com

प्रधानमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक

सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के प्रयासों की समीक्षा की। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उत्पादन को बढ़ाने की कवायद पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए गठित अधिकारियों के अधिकार संपन्न समूहों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उच्चाधिकार प्राप्त समूहों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में संक्रमण की जांच के दिशानिर्देशों व प्रक्रियाओं के ब्योरे पर समीक्षा की गई। देश भर में अब तक 1,45,916 नमूनों की जांच की गई है। पीएमओ के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीपीई के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए क्षमता उन्नयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।

डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पीपीई की कमी के बीच इनकी आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) व नागरिक समाज को भी सक्रिय किया जा रहा है।

बयान के अनुसार, प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ सही ढंग से समन्वय किया जाए, ताकि ओवरलैप (एक ही काम कई व्यक्तियों या एजंसियों द्वारा करना) से बचने के साथ-साथ संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।

प्रधान सचिव ने यह बात रेखांकित की कि आंकड़ों की शुद्धता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, ताकि सभी निर्दिष्ट लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को प्रवासियों और बेघरों जैसे कमजोर समूहों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, केंद्र इस सबंध में राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की बैठक में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) एवं लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों को अपनी फसलों की कटाई में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। सरकार ने 29 मार्च को 11 उच्चाधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था जो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा को बेहतर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने आदि के बारे में सुझाव दे रहे हैं।

कोरोना : सामूहिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना महामारी के मद्देनजर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पूरे देश में, विशेषकर हॉट स्पाट वाले इलाकों में, प्राथमिकता के आधार पर संक्रमण की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि भारत में कोविड-19 की जांच की दर दुनिया भर के देशों की तुलना में सबसे कम है जबकि पिछले कुछ दिनों में इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। इससे पता चलता है कि यह शायद बानगी ही है और हम इसकी गंभीर स्थिति को लेकर बेपरवाह हैं।

यह याचिका तीन वकीलों और कानून के एक छात्र ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है कि इससे प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, उन्हें अलग-थलग करने और उनका उपचार करने के लिए सामूहिक जांच की प्रक्रिया अपनाई जाए। याचिका के अनुसार यह कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए और सबसे पहले उन राज्यों और शहरों में सामूहिक जांच शुरू की जानी चाहिए जहां इस महामारी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का कदम उठाकर ही कोरोना विषाणु महामारी को पूरे देश में फैसले से रोकने में मदद मिलेगी। इस तरह के कदम नहीं उठाने का मतलब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई आग से खेलने जैसी ही हो जाएगी।

याचिका में कहा गया है कि सात अप्रैल की स्थिति के अनुसार भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों में करीब 82 व्यक्तियों की जांच हो रही है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी पर अंकुश पाने के लिए जांच कराने और इसके महत्त्व को इंगित किया है। याचिका में कोरोना विषाणु से निबटने के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष, पीएम-केयर्स और मुख्यमंत्री राहत कोष में आया धन राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष और राज्य आपदा मोचन कोष में स्थानांतरित करने का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका के अनुसार इस कोष का उपयोग कोविड महामारी से निबटने और जांच किट, वेंटिलेटर, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण खरीदने और संक्रमण से प्रभावित होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रखने और उनकी देखरेख वाले केंद्र स्थापित करने के लिए हो सकता है।

स्कूल फीस में छूट को लेकर अभिभावक भ्रम में

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

देश में बंदी की अवधि के दौरान स्कूल की फीस में रियायत की कई राज्य सरकारों की घोषणा पर छात्रों के अभिभावक असमंजस में हैं कि फीस अदा करें या न करें, यह छूट है या रोक। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने घोषणा की है कि स्कूलों द्वारा बंद के दौरान अभिभावकों पर शुल्क अदा करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अभिभावकों के बीच यह स्पष्टता नहीं है कि क्या इस अवधि के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या बाद में उन्हें यह शुल्क अदा करना होगा।

विभिन्न स्कूलों के प्राधिकारियों के मुताबिक, कुछ अभिभावकों ने यह मान लिया है कि इस अवधि के दौरान कोई शुल्क नहीं लगेगा और शुल्क माफी को लेकर उन्हें बहुत से लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। गुड़गांव के रहने वाले संदीप मखीजा ने बताया, 'कोई स्पष्टता नहीं है। स्कूल खाने का खर्च, परिवहन का खर्च समेत कई तरह के शुल्क वसूल रहे हैं। कोई नहीं जानता कि क्या शुल्क माफ किया गया है और क्या नहीं है। जब हमने स्कूल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समय में मिली छूट है रकम में नहीं।' राजस्थान की प्रीति वशिष्ठ की भी ऐसी ही चिंता है। उन्होंने कहा, 'सरकारी परिपत्र कहता है कि स्कूलों को इस अवधि के दौरान कोई अग्रिम शुल्क नहीं लेना चाहिए लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि बाद में फीस देनी होगी या लॉकडाउन की अवधि की फीस नहीं लगेगी।' रजनीश कुमार के दो बच्चे नोएडा के एक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, 'अगर फीस को किसी भी तरह देना ही है तो मैं उसे अभी अपने बजट में किसी तरह समायोजित करने की कोशिश करूंगा न कि बाद में बोझ का सामना करना चाहूंगा। घोषणा के साथ तो यह एक राहत की तरह लग रहा था लेकिन पता नहीं वास्तव में यह है भी कि नहीं। निर्देश स्पष्ट होते तो मददगार रहते।' गुरुग्राम के एक प्रमुख निजी विद्यालय के प्रतिनिधि के मुताबिक, अभिभावक उन्हें फोन कर पूछ रहे हैं कि जब सरकारी आदेश है तो फीस का स्टेटमेंट क्यों जारी किया जा रहा है।

मित्रों की हरसंभव मदद करने को तैयार : प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और ब्राजील से शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने में अपने मित्रों की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और इसे बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के निर्यात को मंजूरी देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया था, जिसके बाद मोदी ने यह बयान दिया।

मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो, आपका शुक्रिया। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्राजील के साझेदारी पहले से मजबूत हुई है।' उन्होंने कहा कि भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ मानवता के संघर्ष में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने नेतन्याहू के ट्वीट के जवाब में कहा, 'हमें इस वैश्विक महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। भारत अपने मित्रों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है।' नेतन्याहू ने गुरुवार शाम को ट्वीट किया था, 'इजराइल को क्लोरोक्वीन भेजने के लिए शुक्रिया, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी। इजराइल के सभी नागरिक आपका धन्यवाद अदा करते हैं।' भारत ने इजराइल को पांच टन दवा सामग्री भेजी है।

कोरोना मृतकों की संख्या 96 हजार के पार

पेज 1 का बाकी

दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 96,344 पहुंच गया। वैश्विक महामारी के कारण आधे से अधिक जान पिछले एक हफ्ते के दौरान गई हैं। लेकिन सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोप और अमेरिका में अधिकारियों ने कहा कि रोज हो रही मौत और सामने आ रहे संक्रमणों का घटना यह उम्मीद बंधाता है कि संभवतः सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया है।

चीन में दिसंबर में पहली बार कोरोना का मामला सामने आने के बाद से 193 देशों और क्षेत्रों में 16 लाख 5250 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में से तीन लाख 31 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। यूरोप में आठ लाख 26 हजार 389 मामले सामने आए और 67 हजार 247 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और कनाडा में संक्रमण के चार लाख 86 हजार 992 मामले हैं और 17 हजार 212 लोगों की मौत हुई है। एशिया में एक लाख 30 हजार 415 मामले हैं और 4603 लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि वैश्विक महामारी की आग अब नियंत्रण में आने लगी है। स्पेन में मृतकों का आंकड़ा गुरुवार को 683 था जो कि एक दिन पहले ही 757 था। देश में 15,000 से ज्यादा लोगों की वायरस के चलते मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता पीछे मुड़कर देखने की नहीं और न ही कम सतर्क रहने की है। फ्रांस में भी रोज के मुकाबले आइसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या कम हो गई है। अब ये आंकड़ा केवल 82 का है। वैश्विक महामारी शुरू होने के बाद से यह पहली गिरावट है।

वैश्विक महामारी पर अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कहा है कि अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,783 मौत हुई जो पिछले दिन के 1,973 के मुकाबले कम थी। अमेरिका में इटली के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा 16,500 मौत हुई है और वहां 4,60,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

ब्रिटेन ने गुरुवार को 881 और लोगों की मौत की जानकारी दी जिससे बाद मृतकों की कुल संख्या 8,000 हो गई है।

आर्थिक मोर्चे पर, यूरोप ने 550 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों के बीच सहमति बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसका मकसद 27 राष्ट्रों के इस गुट खासकर इटली और स्पेन का कुछ बोझ हल्का करना है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अमेरिकावासियों को राहत देने का प्रयास किया है और इसके प्रमुख जेरोम पोवेल ने 2.3 हजार अरब डॉलर के आर्थिक उपायों की घोषणा की है जो बाधित आर्थिक गतिविधि के इस दौर में अधिक से अधिक राहत एवं स्थिरता मुहैया कराएगा। आइएमएफ ने कहा है कि उसके 180 में से 170 सदस्य देश इस साल प्रति व्यक्ति आय में कमी का सामना करेंगे। इससे कुछ ही महीने पहले संस्था ने कहा था कि लगभग हर कोई वृद्धि का स्वाद चखेगा।

आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टालीना जॉर्जिएवा ने कहा कि महामंदी के बाद से हम सबसे बुरी आर्थिक गिरावट का अनुमान जता रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्रों और चीन में उम्मीद बंधाते संकेतों के बावजूद ऐसी आशंका है कि ज्यादातर विकासशील देशों में अभी और बुरा समय आना बाकी है। इसी तरह का भय भारत में भी है जहां करोड़ों गरीब लोग तेजी से निराशा के शिकार होते जा रहे हैं। संकट पर अंतरराष्ट्रीय एकजुटता बनाने के प्रयास में जर्मनी ने गुरुवार को वैश्विक महामारी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र का नेतृत्व किया।

ईपीएफओ ने निपटाए पूर्णबंदी के दौरान 1.37 लाख पीएफ दावे

पेज 1 का बाकी

दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है। कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है। बयान में कहा गया है कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने पिछले दस दिन में इन दावों का निपटान किया है।

ईपीएफओ ने कहा कि उसकी प्रणाली में पूरी तरह से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य श्रेणी में आवेदन किया है, वे भी कोरोना विषाणु संकट से निपटने के लिए केवाईसी अनुपालन की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ से विशेष निकासी का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत 28 मार्च, 2020 को एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना के जरिए ईपीएफ योजना में पैरा 68 एल (3) डाला गया है।

कोरोना के बाद अहम होगा भारत-जापान गठजोड़ : मोदी

पेज 1 का बाकी

मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष केपी ओली के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत-जापान के विशेष सामरिक व वैश्विक गठजोड़ कोविड-19 के बाद विश्व में हमारे लोगों, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दुनिया को नई प्रौद्योगिकी और समाधान विकसित करने में मदद पहुंचा सकते हैं।' जापान के प्रधानमंत्री आबे ने हाल ही में विषाणु को फैलने से रोकने के लिए तोकियो और छह अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की थी। आबे के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष केपी ओली के साथ भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई। मोदी ने ट्वीट में कहा, 'आज नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से बात की। हमने कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की।' ओली ने ट्वीट किया, 'हम कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने एक दूसरे की सीमा पर फंसे नागरिकों की देखभाल की जरूरत पर बल दिया जो दोनों देशों में लागू पूर्ण बंदी की वजह से फंसे हैं।'

वधावन परिवार को महंगी पड़ी तफरीह

पेज 1 का बाकी

समेत कई लोगों ने बुधवार शाम अपनी कारों से खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा की।

पृथक वास में भेजा गया : वधावन परिवार के सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर पुलिस थाने में आइपीसी और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी लोगों को संस्थागत पृथक वास में भेज दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

मामले में कूदी सीबीआइ : कपिल और धीरज वधावन यस बैंक और डीएचएफएल धोखाधड़ी मामलों में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मार्च को पेश होने के लिए यस बैंक मामले में दोनों को समन जारी किए थे, लेकिन दोनों महामारी का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। वधावन बंधुओं के पकड़े जाने के बाद सीबीआइ ने महाराष्ट्र में सतारा जिला प्रशासन को बिना उसकी अनुमति के मुक्त नहीं करने को कहा है, क्योंकि येस बैंक के धोखाधड़ी मामले में वे गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे हैं। येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर और अन्य आरोपियों द्वारा धन की हेराफेरी के संबंध में सीबीआई की प्राथमिकी में दोनों भाइयों के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है।

पंजाब ने एक मई तक बढ़ाई पूर्णबंदी

पेज 1 का बाकी

की बंदिशें बहुत जरूरी हैं ताकि स्वास्थ्य ढांचे पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ न पड़ सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों में यह आम राय है कि पूर्णबंदी ही इस बीमारी के फैलाव को रोकने से बचाव कर सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई की कि इस बीमारी को रोकने वाली कोई दवा/इलाज मिल सके।

मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि कर्फ्यू/लाकडाऊन से धीरे-धीरे बाहर लाने के लिए नीति बनाने के लिए बहुउद्देशीय टास्क फोर्स बनाई जाए। टास्क फोर्स 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टास्क फोर्स में 15 सदस्य होंगे जो व्यापार, कारोबार, उद्योग, कृषि, सिविल सोसायटी और स्वास्थ्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रिमंडल ने टास्क फोर्स के गठन व उसके स्वरूप संबंधी फैसले लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

मंत्रिमंडल ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करने का भी फैसला किया जो कोरोना संकट के खत्म हो जाने और आम जनजीवन की बहाली के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का खाका तैयार करेगी। कैप्टन ने कहा कि वे योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया से इस कमेटी की अध्यक्षता करने का अनुरोध करेंगे। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव में कहा कि केंद्र सरकार से पंजाब में 500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ वायरोलॉजी का एडवांस सेंटर स्थापित करने की मांग की जाएगी। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस मुफ्त में जमीन मुहैया करवाई जाएगी।

मौजूदा संकट से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य ढांचे के तत्काल नवीनीकरण के मकसद से मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक और टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला लिया। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव और पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।

24 घंटे में 37 और लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

बाद गुजरात में 17, मध्य प्रदेश में 16, दिल्ली में 13, पंजाब में 11, तमिलनाडु में आठ, तेलंगाना में सात, आंध्र प्रदेश में छह, कर्नाटक में छह, पश्चिम बंगाल में पांच, जम्मू-कश्मीर में चार, उत्तर प्रदेश में चार, हरियाणा में तीन, राजस्थान में तीन और केरल में दो लोगों की मौत हुई है। वहीं, झारखंड, बिहार, ओड़ीशा और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में 1,364 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 898, तमिलनाडु में 834, तेलंगाना में 473, राजस्थान में 463, उत्तर प्रदेश में 431, आंध्र प्रदेश में 363, केरल में 357, मध्य प्रदेश में 259, गुजरात में 241, कर्नाटक में 197, जम्मू कश्मीर में 184, हरियाणा में 169, पंजाब में 132, पश्चिम बंगाल में 116, बिहार में 60, ओड़ीशा में 44, उत्तराखंड में 35, असम में 29, हिमाचल प्रदेश में 28, चंडीगढ़ में 18, लद्दाख में 15, झारखंड में 13, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 11, छत्तीसगढ़ में 10, गोवा में सात, पुदुचेरी में पांच, मणिपुर में दो, मिजोरम में एक, अरुणाचल प्रदेश में एक और त्रिपुरा में एक मामला सामने आया है।

नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ की साजिश

पेज 1 का बाकी

मुखिया नाम के शख्स ने भारत में दाखिल कराया है। जालिम मुखिया हथियार तस्कर है। वह नेपाल के जिला पारसा के सेरवा थाना अंतर्गत जग्नाथपुर गांव का रहने वाला है। इस बारे में बिहार के गृह सचिव अमीर सुबानी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी गई है।

इस पत्र को लेकर एसएसबी के महानिदेशक ने बताया कि नेपाल से लगी 1,752 किलोमीटर लंबी सीमा पर सभी टुकड़ियों को सतर्क किया जा चुका है, हालांकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू पूर्ण बंदी के चलते सीमा पार से आवाजाही बंद है। उन्होंने कहा कि जब तक इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हो जाता, तब तक हमने सभी टुकड़ियों को सावधान रहने के लिए कहा है। बलों की टुकड़ियों को गश्त और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में नबी करीम, चांदनी महल और जाकिर नगर सील

पेज 1 का बाकी

लिए विभागीय टीमों को उनका टास्क दिया गया है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय व जिला दंडाधिकारी की टीम को जोड़ा गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार है जो क्वारंटाइन किए जाने के लिए है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना निर्धारित क्षेत्र छोड़ता तो संबंधित अधिकारी को स्वतः ही सूचना पहुंच जाएगी। यह संक्रमण रोकने में मददगार होगा।

पांच जोन हैं संक्रमण के रडार पर : दिल्ली में संक्रमण के रडार पर सबसे ऊपर 11 में से पांच जिले हैं। इन जिलों सबसे अधिक संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस समय उत्तरी जिले 970, दक्षिण-पश्चिम में 611, मध्य में 233, पश्चिम में 127, उत्तर-पश्चिम में 194 व दक्षिण में 119 लोग पृथक हैं। दिल्ली के सभी जिलों में ऐसे लोगों की संख्या 2565 है। ये सभी 16 केंद्र में रखे गए हैं।

यूपी में 4.81 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार डाले

पेज 1 का बाकी

अधिकारियों के मुताबिक यह राशि मजदूरों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों को भोजन और भरण-पोषण के लिए सरकार नकद राशि मुहैया करा रही है। इसमें रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदारों को एक-एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता सरकार की तरफ से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं।

राज्य सरकार 35 लाख मजदूरों के भरण-पोषण के लिए भी राशि को सीधे बैंक खातों में भेज चुकी है। इनमें 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक शामिल हैं, जिनके बैंक खाते में एक-एक हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 1.65 करोड़ से ज्यादा अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को एक माह का निशुल्क राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत 20.37 लाख श्रमिकों को भरण पोषण के रूप में एक-एक हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से राशन वितरित किया जा रहा है।

मूलचंद अस्पताल में मरीज व नर्स मिले संक्रमण के शिकार

पेज 1 का बाकी

मिले दोनों संक्रमितों के संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इलाज में लगे डॉक्टरों की भी जांच कराई जा सकती है। अस्पताल प्रशासन इन दोनों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने व उनको पृथक करने में लगा हुआ है। प्रशासन ने अस्पताल से सभी की सूची मांगी है।

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के तीन कैंसर मरीजों की जांच में भी कोरोना की पुष्टि के बाद जहां प्रशासन में चिंता बढ़ गई थी, वहीं इनमें से एक कैंसर मरीज की मौत से हड़कंप मच गया है। संक्रमण की पुष्टि के बाद इन मरीजों को इलाज के लिए तैयार किए राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मरीज की मौत राजीव गांधी में ही हुई है। बाकी मरीजों के जांच के नमूने आने हैं। इसके पहले अस्पताल के डॉक्टरों सहित कई कर्मचारी मिलाकर कुल 21 स्वास्थ्यकर्मी चपेट में आ चुके हैं। इनको भी राजीव गांधी में भर्ती किया गया है। कैंसर संस्थान को सील किया जा चुका है।

राममनोहर लोहिया अस्पताल में चार और डॉक्टरों को पृथक किया गया है। इन डॉक्टरों ने जिन मरीजों का इलाज किया है उनमें से कुछ मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद से इन चारों डॉक्टरों को भी निगरानी में भेज रखा गया है।

गंगाराम अस्पताल के पहले 108 और बाद में छह और कर्मियों को पृथक किया गया था। इनमें से दो डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके पहले यहां पर दो मरीजों का इलाज किया गया था जिनमें बाद में कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से संपर्क में आए सभी लोग अलग रखे गए हैं।

कोरोना के इलाज के लिए चिह्नित इस अस्पताल में इलाज के काम में लगे एक नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। उनको इसी अस्पताल में आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। इस अस्पताल में एक साथ कई लोगों के कोरोना के चपेट में आने व प्रशासन को बताए बगैर कोरोना मरीज का शव परिजनों को सौंपे जाने के मामले में गंभीर कार्रवाई की गई है। वेंकटेश्वर अस्पताल में भी एक कोरोना मरीज की गुरुवार को मौत हो गई। इसके अलावा एम्स व सफदरजंग के डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

पूर्णबंदी बढ़ाने पर प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से चर्चा

पेज 1 का बाकी

सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेज रखा है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे समय में होने जा रही है जब कई विशेषज्ञों ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 25 मार्च को लागू 21 दिनों की देशव्यापी पूर्णबंदी को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए।

अधिकारियों के मुताबिक, माना जा रहा है कि अगर पूर्णबंदी की अवधि बढ़ेगी तो उसमें कुछ क्षेत्रों को सीमित छूट मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय तक यह स्थिति बने रहने से बड़े पैमाने पर विषम आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्यों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध जारी रहेंगे। स्कूल-कॉलेज और धर्मस्थल बंद रहने की संभावना है। हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, सरकार के लिए हर किसी की जान बचाना प्राथमिकता है। अधिकारियों के मुताबिक, पूर्ण बंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हो रहा है, ऐसे में कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित दूरी का पालन करने की शर्त पर छूट दी जा सकती है। सबसे ज्यादा असर उड्डयन क्षेत्र पर पड़ा है। ऐसे में सरकार उड़ान सेवा प्रदाता कंपनियों को उड़ानें शुरू करने की छूट दे सकती है, लेकिन उन्हें सभी क्लास में बीच की सीट खाली रखनी होगी।

केंद्रीय स्तर पर पूर्ण बंदी की अवधि बढ़ाने से पहले इस आशय की घोषणा करने वाला ओड़ीशा पहला राज्य बन गया है। उसने गुरुवार को 30 अप्रैल तक पूर्ण बंदी और 17 जून तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। पंजाब ने शुक्रवार को इस तरह की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने का सुझाव केंद्र को भेजा है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से मांगे सुझाव

पेज 1 का बाकी

पुथांडु, महा विशुभा, संक्राति आदि भी अप्रैल में हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर उचित निगरानी रखी जानी चाहिए। पूर्ण बंदी का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर कानून प्रवर्तन एजंसियों को आपदा प्रबंधन कानून-2005 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से कहा कि बंद के विभिन्न पहलुओं से उसे अवगत कराएं और यह भी बताएं कि क्या कुछ ज्यादा श्रेणी में लोगों और सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दिए जाने की जरूरत है।

बिहार सहित कुछ राज्यों ने गृह मंत्रालय को पत्र का जवाब दिया है। राज्य सरकारों के सुझावों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति देना भी शामिल है।

www.readwhere.com

मानसून से पहले की खरीफ फसलों की बुवाई शुरू

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

अभी तक 32.58 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया, जो पिछले साल इसी अवधि के 23.81 लाख हेक्टेयर के रकबे से 27 फीसद अधिक है।

कोविड–19 विषाणु प्रकोप के कारण लागू पूर्णबंदी के बीच देशभर में मानसून से पहले खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। इसमें धान की खेती का रकबा पिछले सत्र की तुलना में 27 फीसद बढ़कर 32.58 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

बुवाई का काम, दक्षिण–पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) की शुरुआत के साथ गति पकड़ेगा। मानसून के दौरान देश की कुल वर्षा का लगभग 70 फीसद बारिश होती है। खरीफ में दलहन और तिलहन के अलावा धान मुख्य खरीफ फसल होती है। मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, किसानों ने शुक्रवार तक 32.58 लाख हेक्टेयर में धान बोया है, जो पिछले साल इसी अवधि के 23.81 लाख हेक्टेयर के रकबे से 27 फीसद अधिक है। खरीफ मौसम जून से शुरू होता है और सितंबर माह में समाप्त होता है। बुवाई का काम मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में 3.13 लाख हेक्टेयर, असम में 2.73 लाख हेक्टेयर, कर्नाटक में 1.64 लाख हेक्टेयर और छत्तीसगढ़ में 1.50 लाख हेक्टेयर रकबे में हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु में बुवाई का रकबा 1.30 लाख हेक्टेयर है, जबकि बिहार में 1.22 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 0.65 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 0.59 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 0.54 लाख हेक्टेयर और केरल में 0.46 लाख हेक्टेयर हैं। समीक्षाधीन अवधि में दलहन बुवाई का रकबा बढ़कर पहले के 3.01 लाख हेक्टेयर से 3.97 लाख हेक्टेयर हो गया। इसमें से 2.59 लाख हेक्टेयर में हरा चना और 1.23 लाख हेक्टेयर में काला चना बोया गया है और 0.15 लाख हेक्टेयर में अन्य दलहनी फसलें लगाई गई हैं। इसी तरह, मोटे अनाजों का रकबा एक साल पहले 4.33 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल के चालू खरीफ सत्र में अब तक 5.54 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। इसमें से 2.81 लाख हेक्टेयर में मक्का और 2.51 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई की गई है।

तिलहन मामले में भी समीक्षाधीन अवधि में बुवाई का रकबा पहले के 5.97 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें से मूंगफली 4.08 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जबकि 2.13 लाख हेक्टेयर में तिल की बुवाई हुई है। सभी खरीफ फसलों के तहत खेती का कुल रकबा इस वर्ष अब तक बढ़कर 48.76 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो रकबा पिछले साल 37.12 लाख हेक्टेयर था। कोविड–19 की रोकथाम के लिए सरकार ने किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के समय किसी भी संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के अलावा बुवाई के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।

कोरोना के कारण और बिगड़ी एअर इंडिया की माली हालत : बंसल

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा)।

सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया के प्रमुख राजीव बंसल ने गुरुवार को कहा कि कोरोना विषाणु ने कंपनी की पहले से खराब आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

हालांकि, कंपनी किसी तरह से अपना परिचालन जारी रखे हुए है। बंसल ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि महामारी के दौरान राहत व बचाव के लिए विशेष उड़ानें शुरू करने में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एअर इंडिया कोविड–19 महामारी शुरू होने के काफी पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। महामारी के त्रासद प्रभावों विशेषकर विमानन क्षेत्र पर पड़े असर ने कंपनी की माली हालत और खराब कर दी है। इसके बाद भी आपकी कंपनी ने परिचालन बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बंसल ने कर्मचारियों को याद दिलाया कि कंपनी हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य कंपनी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से जूझने के लिए कंपनी कर्मचारियों को सुरक्षा व बचाव के सारे साधन मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि बचाव के सारे उपाय करने के साथ ही कंपनी आपकी सुरक्षा के लिए पीपीई मुहैया करा रही है।

केंद्र ने दैनिक खरीद सीमा को प्रति किसान 40 क्विंटल किया

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

केंद्र सरकार ने कोविड–19 के कारण पूर्ण बंदी की वजह से फसल कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी कम होने को देखते हुए किसानों की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कृषि फसलों की दैनिक खरीद सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ा कर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है।

कुछ राज्यों द्वारा जल्द खराब होने की संभावना वाली फसलों की कम कीमत होने को लेकर व्यक्त की गई चिंता के बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इन राज्यों से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत खरीद प्रस्ताव भेजने को कहा था। प्रत्यक्ष खरीद या पीएसएस योजना तब लागू की जाती है, जब दाल, तिलहन और नारियल गरी की कीमतें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं। इसके तहत केंद्र उत्पादन के 25 फीसद तक के खरीद व्यय और नुकसान का बोझ वहन करता है।

वहीं, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को जल्द खराब होने की संभावना वाली फसलों और बागवानी फसलों की खरीद करने के लिए उस समय लागू किया जाता है, जब पिछले सामान्य वर्ष के मुकाबले कीमतों में 10 फीसद तक कमी आ जाती है। इस स्थिति में घाटा होने पर राज्यों को नुकसान का 50 फीसद बोझ वहन करना होता है।

सरकार की इन योजनाओं के तहत खरीद का काम करने वाली प्रमुख एजंसी, सहकारी संस्था नाफेड को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि इस साल रबी फसलों के लिए पीएसएस के तहत खरीद की दैनिक सीमा 25 क्विंटल से बढ़ा कर 40 क्विंटल प्रति व्यक्ति कर दी गई है। मंत्रालय ने नाफेड को, खरीद के आंकड़ों के शुरू होने से 90 दिनों की अवधि के लिए पीएसएस के तहत तिलहन और दलहन खरीदने को भी कहा है, जिस बारे में फैसला संबंधित राज्य द्वारा किया जा सकता है।

जहां तक एमआईएस का सवाल है, मंत्रालय ने अलग से जारी एक परिपत्र में राज्यों को कहा है कि अगर कीमतों में गिरावट दिखाई देती है तो वे इस योजना के तहत जल्द खराब होने वाली कृषि फसलों और बागवानी उत्पादों की प्रत्यक्ष खरीद के कार्यान्वयन के लिए अपना प्रस्ताव भेजें।

अफगानिस्तान, लेबनान को नाफेड के जरिए निर्यात किया जाएगा 90,000 टन गेहूं

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह 90,000 टन गेहूं का अफगानिस्तान और लेबनान को निर्यात करेगा। यह मामल सरकार के पास पड़े अतिरिक्त भंडार से किया जाएगा और सरकारों के बीच द्विपक्षीय करार के तहत किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास अपनी जरूरत से ज्यादा गेहूं है। फसल अच्छी है। विभिन्न देशों से विशेष मांग पर सहकारी संस्था नाफेड से अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं और लेबनान को 40,000 टन गेहूं का निर्यात करने को कहा गया है।'' सरकारी गोदामों में मार्च अंत में लगभग 2.3 करोड़ टन गेहूं और 5.4 करोड़ टन चावल था जो इसकी आवश्यकता से बहुत अधिक है। नई फसल की आवक शुरू हो गई है। किसानों ने अब तक बोए गए कुल रकबे में से लगभग 33 फीसद भाग में गेहूं फसल की कटाई पूरी कर ली है। अच्छी बारिश होने के कारण फसलवर्ष 2019–20 में भारत में 10 करोड़ 62.1 लाख टन गेहूं उत्पादन का नया रेकॉर्ड बनने का अनुमान है। अधिकतम वार्षिक उत्पादन का पिछला रिकॉर्ड 2018–19 (जुलाई–जून) में बना था। उस साल 10 करोड़ 36 लाख टन की फसल थी।

पीएम-किसान की पहली किस्त वितरित, 7.92 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 15,841 करोड़

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना की पहली किस्त के तहत चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही कुल 7.92 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 15,841 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर चुकी है। यह जानकारी शुक्रवार को कृषि मंत्रालय के एक बयान में दी गई।

इस योजना के तहत उच्च आय वाले किसानों को छोड़ कर सभी किसानों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 2000– 2000 रुपए की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार ने कोराना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त शुरू में ही वितरित करने का फैसला किया। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण 24 मार्च से लागू पाबंदियों के बीच किसान सम्मान निधि योजना से 7.92 करोड़ किसान परिवारों को फायदा पहुंचाया गया है। उनके खातों में कुल 15,841 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी रोक के बीच सरकार ने 27 मार्च को वादा किया था कि वह पीएम किसान की पहली किस्त के 2000–2000 रुपये इस योजना के पात्र 8.69 करोड़ किसानों को उनके खातों में नए वित्त वर्ष के पहले सप्ताह में ही डालेगी।

मेक्सिको की सहमति के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर करार 'नजदीक'

दुबई, 10 अप्रैल (एपी)।

यदि यह करार होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता लाने की दृष्टि से काफी ऐतिहासिक कदम होगा।

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस सहित अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के लिए उत्पादन में प्रतिदिन एक करोड़ बैरल की कटौती करने पर सहमति बन गई है। अमेरिका सहित कई अन्य देश शुक्रवार को अपना उत्पादन घटाने पर बात कर रहे थे। यदि यह करार होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता लाने की दृष्टि से काफी ऐतिहासिक कदम होगा।

ओपेक और भागीदार देशों के बीच करार के तहत जुलाई तक कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन एक करोड़ बैरल की कटौती की जाएगी। साल के अंत तक उत्पादन में 80 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती होगी। वर्ष 2021 की शुरुआत से 16 माह तक उत्पादन में 60 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की जाएगी। शुरुआत में मेक्सिको ने इस करार में अड़चन डाली थी लेकिन अब मेक्सिको ने अपनी सहमति दे दी है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्रैडॉर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मेक्सिको उत्पादन में प्रतिदिन 1,00,000 बैरल की कटौती करेगा।' उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे संपर्क किया था। ओपेक करार के तहत मेक्सिको को अपने उत्पादन में 4,00,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करनी थी। लेकिन मेक्सिको 1,00,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करना चाहता था। लोपेज ने कहा कि ट्रंप ने इस बात पर सहमति दी है कि मेक्सिको की भरपाई के लिए अमेरिका अपने उत्पादन में 2,50,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करेगा।

मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्रैडॉर ने कहा कि मेक्सिको उत्पादन में प्रतिदिन 1,00,000 बैरल की कटौती करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे संपर्क किया था। ओपेक करार के तहत मेक्सिको को अपने उत्पादन में 4,00,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करनी थी। लेकिन मेक्सिको 1,00,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करना चाहता था। लोपेज ने कहा कि ट्रंप ने इस बात पर सहमति दी है कि मेक्सिको की भरपाई के लिए अमेरिका अपने उत्पादन में 2,50,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करेगा। इससे करार का रास्ता साफ हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन कटौती अनुमानतः 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन पर पहुंच सकती है जो वैश्विक उत्पादन का 15 प्रतिशत बैठेगा। यह कदम आकार और इसमें भागीदार देशों की संख्या दोनों के हिसाब से ऐतिहासिक होगा। इनमें से कई देश ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी हैं। इस साल की शुरुआत से कच्चे तेल का दाम करीब 50 प्रतिशत नीचे आ चुका है। हालांकि, यह उपभोक्ताओं की दृष्टि से अच्छा है लेकिन कई देशों और कंपनियों के लिए यह उत्पादन की लागत से कम हो गया है। इससे तेल उत्पादक राष्ट्रों के बजट पर दबाव बन गया है। विश्लेषकों ने आगाह किया है कि प्रस्तावित कटौती के बावजूद दीर्घावधि में मांग में कमी की भरपाई हो पाना संभव नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की मांग में भारी गिरावट आई है।

(This is only an advertisement for information purposes and not a Prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India)

LAXMI

LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED

Corporate Identity Number : U36911GJ2010PLC059127

Our Company was originally incorporated on January 07, 2010 as "**Laxmi Goldorna House Private Limited**" vide Registration No. 059127/ 2009-2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Further, our Company was converted into Public Limited Company and consequently name of company was changed from "**Laxmi Goldorna House Private Limited**" to "**Laxmi Goldorna House Limited**" vide Special resolution passed by the Shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on July 08, 2017 and a fresh certificate of incorporation dated July 25, 2017 issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For further details please refer to chapter titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 103 of the Prospectus.

Registered Office: Laxmi House, Opp. Bandharano Khacho, M G Haveli Road, Manek Chowk, Ahmedabad, Gujarat-380001, India
Corporate Office: Block No.58/106-107-108, Anandnagar Flats, B/h Venus Atlantis, Prahladnagar, Satellite, Ahmedabad-380015, Gujarat, India
Tel No: +91-79-2214 9482, +91-9898 033044, **E-mail**: info@laxmilifestyle.co.in, **Website**: www.laxmilifestyle.co.in
CONTACT PERSON: MR. JAY RAMESHCHANDRA DHOLAKIA (COMPANY SECRETARY & COMPLAINCE OFFICER)

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAYESH CHINUBHAI SHAH AND MRS. RUPALBEN JAYESHKUMAR SHAH

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 55,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED ("OUR COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 5.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 828.00 LAKHS ("ISSUE") OF WHICH 2,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 43.20 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 52,32,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 784.80 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.45% AND 25.07%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 187 OF THE PROSPECTUS.

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS"), AS AMENDED, IN TERMS OF RULE 19(2)(B)(I) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR"), THIS ISSUE IS BEING MADE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 15.00. THE ISSUE PRICE IS 1.5 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, MARCH 20, 2020 AND ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, APRIL 03, 2020*

* The Issue was originally scheduled to close on Thursday, March 26, 2020. The Issue closing was extended by 5 (five) additional working days to closed on Friday, April 03, 2020.

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). Our Company has received an approval letter dated February 13, 2020 from NSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited. The trading is proposed to be commenced on or about April 16, 2020.*

*Subject to receipt of listing and trading approvals from the National Stock Exchange of India Limited.

All Applicants were allowed to participate in the issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process by providing the details of the respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs").

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue has received 105 applications for 59,20,000 Equity Shares resulting in 1.07 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the applications received in the issue (before technical rejections) are as follows:

Detail of the Applications Received (Before Technical Rejection but after application not banked) :

Category	Number of Applications	%	Number of Equity Shares	%	SUBSCRIPTION (TIMES)
Market Makers	01	0.95	2,88,000	4.86	1.00
Retail Individual Investor's	57	54.29	4,56,000	7.70	0.17
Other than Retail Individual Investors	47	44.76	51,76,000	87.43	1.98
TOTAL	105	100.00	59,20,000	100.00	1.07

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares
Market Makers	Nil	Nil
Retail Individual Investors	1	8,000
Other than Retail Individual Investors	1	16,000
Total	2	24,000

After eliminating technically rejected applications, the following tables give us category wise net valid applications:

Category	Number of Applications	%	Reserved Portion (as per Prospectus)	No. of Valid Shares applied	% of Total Applied	Subscription (Times)
Market Maker	1	100	2,88,000	2,88,000	100	1.00
Total	1	100	2,88,000	2,88,000	100	1.00

Category	Number of Applications	%%	Reserved Portion (as per Prospectus)	Proportionate Issue Size (After rounding off)	No. of Valid Shares applied	% of Total Applied	Subscription (Times)
Retail Individual Investors	56	54.90	26,16,000	4,48,000	4,48,000	7.99	0.17
Other than Retail Individual Investors	46	45.10	26,16,000	47,84,000	51,60,000	92.01	1.97
Total	102	100.00	52,32,000	52,32,000	56,08,000	100.00	

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – National Stock Exchange of India Limited on April 08, 2020

A. **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 15 per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 2,88,000 Equity shares

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: before Rounding Off	Allocation per Applicant: After Rounding Off	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 1	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 2	Number of Successful Applicants (After Rounding Off)	Total No. of Shares allocated/ allotted	Surplus / Deficit
2,88,000	1	100.00	2,88,000	100.00	2,88,000	2,88,000	2,88,000	1	1	1	2,88,000	--
TOTAL	1	100.00	2,88,000	100.00	2,88,000	2,88,000	2,88,000	1	1	1	2,88,000	--

B. **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 15 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 0.17 times i.e. for 4,48,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 4,48,000 Equity Shares to 56 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: before Rounding Off	Allocation per Applicant: After Rounding Off	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 1	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 2	Number of Successful Applicants (After Rounding Off)	Total No. of Shares allocated/ allotted	Surplus / Deficit
8000	56	100.00	4,48,000	100.00	26,16,000	46714.28	8000	1	1	56	4,48,000	-21,68,000
TOTAL	56	100.00	4,48,000	100.00	26,16,000					56	4,48,000	-21,68,000

C. **Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 15 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.97 times i.e. for 51,60,000 shares the total number of shares allotted in this category is 47,84,000 Equity Shares to 46 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: before Rounding Off	Allocation per Applicant: After Rounding Off	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 1	Ratio of Allottees to the Applicants Ratio 2	Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful Applicants (After Rounding Off)	Total No. of Shares allocated/ allotted	Surplus / Deficit
16000	13	28.26	208000	4.03	192843	14834.08	8000	1	1		13	104000	-88843
							8000	11	13	1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13		88000	88000
24000	4	8.69	96000	1.86	89005	22251.25	16000	1	1		4	64000	-25005
							8000	3	4	1,2,4		24000	24000
32000	2	4.34	64000	1.24	59337	29668.50	32000	1	1		2	64000	4663
40000	5	10.86	200000	3.87	185426	37085.20	32000	1	1		5	160000	-25426
							8000	3	5	1,2,3		24000	24000
56000	1	2.17	56000	1.08	51919	51919.00	56000	1	1		1	56000	4081
64000	3	6.52	192000	3.72	178009	59336.33	56000	1	1		3	168000	-10009
							8000	1	3	2		8000	8000
88000	1	2.17	88000	1.7	81588	81588.00	80000	1	1		1	80000	-1588
112000	1	2.17	112000	2.17	103839	103839.00	104000	1	1		1	104000	161
120000	2	4.34	240000	4.65	222512	111256.00	112000	1	1		2	224000	1488
136000	4	8.69	544000	10.54	504360	126090.00	120000	1	1		4	480000	-24360
							8000	3	4	2,3,4		24000	24000
144000	2	4.34	288000	5.58	267014	133507.00	136000	1	1		2	272000	4986
200000	1	2.17	200000	3.87	185426	185426.00	184000	1	1		1	184000	-1426
208000	1	2.17	208000	4.03	192843	192843.00	192000	1	1		1	192000	-843
224000	1	2.17	224000	4.34	207678	207678.00	208000	1	1		1	208000	322
296000	1	2.17	296000	5.73	274431	274431.00	272000	1	1		1	272000	-2431
312000	2	4.34	624000	12.09	578530	289265.00	288000	1	1		2	576000	-2530
320000	1	2.17	320000	6.20	296682	296682.00	296000	1	1		1	296000	-682
1200000	1	2.17	1200000	23.25	1112558	1112558.00	1112000	1	1		1	1112000	-558
TOTAL	46	100	5160000	100	4784000						46	4784000	0

The Board of Directors of the Company at its meeting held on April 08, 2020 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and in meeting held on April 09, 2020 has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN-cum-allotment advices and/or notices will forwarded to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before April 15, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will processed on or prior to April 15, 2020 In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (NSE EMERGE) within six working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated March 11, 2020 ("Prospectus")

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED at www.kfintech.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

KFINTECH
KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
SEBI Registration Number: INR000000221
Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad–500 032, Telangana, Tel No.:+91-040-6716 2222, Fax No.: +91-040-2343 1551
Email: laxmi.ipo@kfintech.com, Investor grievance Email – einward.ris@kfintech.com
Website: www.kfintech.com, Contact Person: Mr. M Murali Krishna

Date : April 10, 2020
Place : Ahmedabad

For, **LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Jayesh Chinubhai Shah
Chairman & Managing Director
DIN - 02479665

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF **LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED.**

Laxmi Goldorna House Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadar and Nagar Haveli. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.beelinebroking.com, website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.laxmilifestyle.co.in Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 18 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Garima Advt

www.readwhere.com

खबर कोना

फुटबॉल खिलाड़ी नोर्मन हंटर (फाइल फोटो)

कोविड-19 की चपेट में इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हंटर

लंदन, 10 अप्रैल (एएफपी)।

इंग्लैंड और लीड्स के पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नोर्मन हंटर का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। लीड्स युनाइटेड क्लब के लिए 540 मैच खेलने वाले 76 साल के हंटर दो बार इंग्लैंड के घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट के चैंपियन रहे हैं। लीड्स की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि लीड्स युनाइटेड और इंग्लैंड के दिग्गज हंटर कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हंटर ने इंग्लैंड के लिए 28 मैच खेले हैं और वह 1966 में फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे हालांकि उन्हें मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला था।

जापान का सूमो पहलवान कोरोना विषाणु से संक्रमित

तोक्यो, 10 अप्रैल (एएफपी)।

जापान सूमो संघ ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उनका एक पहलवान कोरोना विषाणु से संक्रमित पाया गया है। जापान में सूमो की प्रतियोगिताएं काफी लोकप्रिय हैं लेकिन कोविड-19 के कारण उसे अपना एक टूर्नामेंट बंद स्टेडियम में आयोजित करना पड़ा जबकि अन्य टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। संघ ने कहा कि उनके एक पहलवान को पिछले सप्ताह बुखार था और उसे वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस पहलवान की पहचान उजागर नहीं की गई है। संघ ने कहा कि किसी भी अन्य पहलवान और अधिकारी में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए हैं तथा संक्रमित पहलवान के संपर्क में रहने वाले लोगों को घर में रहने और स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

पापुआ न्यूगिनी, आयरलैंड ने क्वालीफाई किया

तोक्यो, 10 अप्रैल (एपी)।

कोरोना वायरस महामारी के बीच तोक्यो ओलंपिक के मुख्य कार्यकारी ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि खेल 16 महीने के विलंब के बाद अगले साल भी हो सकेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस सप्ताह आपात घोषणा करके पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। तोक्यो आयोजन समिति के सीईओ तोशिरो मुतो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह कहने की स्थिति में होगा कि अगले साल जुलाई में भी खेल हो सकेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपको स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। तोक्यो ओलंपिक अब 23 जुलाई 2021 से और पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से होंगे। आबे पर कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देर से कदम उठाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह इसी साल ओलंपिक कराना चाहते थे।

कोरोना : राशि जुटाएंगे पूर्व ओलंपिक चैंपियन फ्रोडेनो

बर्लिन, 10 अप्रैल (भाषा)।

जर्मनी के पूर्व ओलंपिक चैंपियन जॉन फ्रोडेनो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए राशि जुटाने के मकसद से घर में आयरन मैन चैलेंज को पूरा करेंगे। जेनेवा (स्पेन) स्थित अपने घर में वह शनिवार को सुबह छह बजे (भारतीय समयनुसार सुबह 11:30 बजे) इसे शुरू करेंगे जिसका ऑनलाइन माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान वह अपने घर के तरणताल में तैराकी कर 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके बाद अभ्यास करने वाली बाइक को 180 किलोमीटर तक चलाएंगे और फिर ट्रेडमील पर दौड़कर मैराथन (42 किलोमीटर) पूरा करेंगे। बेजिंग ओलंपिक में ट्रायथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं इसके जरिए उन लोगों का समर्थन करना चाहता हूं जो इन दिनों हर रोज अस्पताल में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का एफआइएच प्रो लीग रद्द

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

एफआइएच प्रो लीग में भारत का अगले महीने होने वाला आखिरी दौर का घरेलू मुकाबला कोरोना विषाणु के कारण रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड पुरुष हॉकी टीम ने यात्रा संबंधी पाबंदियों के कारण एशियाई चरण रद्द कर दिया था।

भारत को 23 और 24 मई को भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड से खेलना था। न्यूजीलैंड ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया है।

हॉकी न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी इयान फ्रांसिस ने कहा, न्यूजीलैंड सरकार द्वारा लगाई गई यात्रा संबंधी पाबंदियों और सरकारी लॉकडाउन के साथ ही डाक्टरों की सलाह के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि हमारी पुरूष टीम भारत का और महिला टीम चीन का

मुकाबला 23 और 24 मई को भुवनेश्वर में खेला जाना था

दौरा नहीं करेगी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ ने प्रो लीग मैचों का सत्र जुलाई अगस्त तक बढाने के संकेत दिए थे। एफआइएच ने कोरोना महामारी के कारण सारे मैच 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिए थे लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। भारत एफआइएच प्रो लीग में पदार्पण के साथ चौथे स्थान पर है जबकि न्यूजीलैंड छठे स्थान पर है।

भारत ने दो मैच जीते और एक हारा है। हॉकी इंडिया की सीईओ एलेना नार्मन ने मैच रद्द होने पर निराशा जताई लेकिन न्यूजीलैंड के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, यह निराशाजनक है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच रद्द हो गए हैं लेकिन हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। हर राष्ट्रीय खेल महासंघ की प्राथमिकता अपने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा है। हॉकी इंडिया ने बताया कि इन मैचों के टिकट खरीद चुके दर्शकों को पूरा पैसा वापिस मिलेगा।

महिला अंडर-17 विश्व कप

तारीखों के लिए फीफा के संपर्क में है फुटबॉल महासंघ : पटेल

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अंडर-17 महिला विश्व कप की नई तारीखों को अंतिम रूप देने के साथ ही भाग लेने वाले खिलाड़ियों की मूल आयु मानदंड को बनाए रखने के लिए महासंघ फीफा के साथ चर्चा कर रहा है।

भारतीय अंडर-17 महिला टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। इस अंडर-17 विश्व कप का आयोजन भारत में नवंबर में होना था लेकिन दुनियाभर में कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। पटेल ने कहा कि स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) फीफा के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि 'जल्द से जल्द संभावित तारीखों' की घोषणा की जा सके। पटेल ने ट्वीट किया, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि हम अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी के

लिए एक नई और जल्द से जल्द संभावित तारीख को तय करने के लिए फीफा के साथ काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए एलओसी और फीफा नई तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे है। पटेल ने कहा, हम अंडर-17 महिला विश्व कप की उम्र के मानदंड को मूल रूप से रखने के लिए भी फीफा के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि जिन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत की है , वे खेलने के अवसर से ना चूकें। इस टूर्नामेंट का आयोजन दो से 21 नवंबर तक होना था जहां मैचों को कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाना था।

खाना पकाना सीख रहीं दीपिका

कोलकाता, 10 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी पूर्ण बंदी के कारण रेंज पर निशाना लगाने का अभ्यास नहीं कर सकतीं। ऐसे में वे इस समय का इस्तेमाल मंगेतर और साथी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज अतनु दास के लिए मांसाहारी खाना विशेषकर चिकन पकाना सीखकर कर रही हैं।

दो साल पहले दोनों की सगाई हुई थी और शादी से पहले दोनों तोक्यो ओलंपिक पर ध्यान लगाना चाहते थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक के 2021 तक स्थगित होने के बाद अब लगता है कि उनकी शादी इनसे पहले ही हो जाएगी।

दीपिका ने कहा कि चावल और दाल पकाना आता था। अब मांसाहारी (विशेषकर चिकन) खाना बनाना सीख रही हूं। यह पूछने पर कि उनकी मां कुछ 'ऑनलाइन टिप्स' दे रही हैं कि चिकन कैसे बनाया जाता है तो उन्होंने कहा, 'मैं दिन की शुरुआत प्राणायम से करती हूं और फिर 45 मिनट तक अभ्यास करती हूं। नाश्ते के बाद खाना पकाना सीखती हूं।'

हालांकि पूर्व नंबर एक तीरंदाज ने कहा कि उन्होंने हॉल में पांच मीटर की रेंज बना ली है जिसमें दोनों दोपहर में करीब दो घंटे तक अभ्यास करते हैं, हालांकि लॉकडाउन से पहले वास्तविक अभ्यास शुरू नहीं होने वाला। दीपिका ने कहा कि हम एक निशाना बनाकर डेढ़ से दो घंटे अभ्यास करते हैं। यह हालांकि रेंज की तरह का अभ्यास नहीं है। लेकिन हम अभ्यास करते हैं और घर पर ही रह रहे हैं।

अनुबंधित खिलाड़ियों का बीसीसीआइ ने बकाया राशि का भुगतान किया

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की तिमाही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। उसने कहा कि कोविड-19 के कारण बनी अनिश्चितता के बावजूद वह किसी को परेशान नहीं होने देगा। वहीं इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती के संकेत दिए हैं।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन 24 मार्च को घोषित किया गया और इसके बावजूद बीसीसीआइ किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार था। बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की केंद्रीय अनुबंध भुगतान की तिमाही किश्त चुका दी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस दौरान भारत या भारत ए की

तरफ से खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का मैच शुल्क ये सभी बकाए वित्तीय वर्ष के आखिर तक चुका दिए गए हैं।

इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वे वेतन में कटौती के लिए तैयार हैं। आस्ट्रेलिया में केंद्रीय अनुबंध की घोषणा टाल दी गई है जबकि इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट ने यार्कशर के अपने साथियों सहित सरकारी अवकाश पर जाने के लिए आवेदन किया है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार वेतन का 80 फीसद का भुगतान करती है जो कि 2500 पौंड तक हो सकती है।

बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि जब अन्य बोर्ड इस मुश्किल घड़ी में अपने घरेलू खिलाड़ियों को भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब भारतीय बोर्ड की मजबूत वित्तीय स्थिति से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को सरकारी अवकाश (सरकारी सहायत कार्यक्रम) पर रख दिया है। हर जगह वेतन में कटौती की बात चल रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि बीसीसीआइ हमेशा की तरह अपने खिलाड़ियों की अच्छी तरह से देखभाल करने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि हमारे अंतरराष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेटरों को परेशानी नहीं होगी। अधिकारी ने इस पर सहमति जताई कि इस साल के आखिर तक आइपीएल का होना जरूरी है क्योंकि अगर यह नहीं होता है तो सभी शेयरधारकों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।

विंडीज को बुलंदी पर ले जा सकते हैं पूरन, हेटमायर और होप

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

दिग्गज क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने उम्मीद जताई है कि निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर और शाई होप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फिर से बुलंदी पर ले जा सकते हैं।

होल्डिंग ने कहा कि इन युवा क्रिकेटरों के कारण उन्हें उम्मीद की रोशनी दिख रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन युवा प्रतिभाओं को ठीक से प्रशिक्षण दिया जाता है तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट फिर से बुलंदी पर पहुंच सकता है।

होल्डिंग ने कहा कि मुझे उम्मीद की किरण दिख रही है क्योंकि मैं उनकी प्रतिभा को देख रहा हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस प्रतिभा के साथ कैसे न्याय करते हैं। अगर हम इन प्रतिभाओं से सर्वश्रेष्ठ

माइकल होल्डिंग को उम्मीद

लेने में सफल रहे तो एक अच्छी टीम का गठन कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा से तभी अच्छा परिणाम मिल सकता है जब टीम अच्छा करे।

होल्डिंग ने कहा कि पूरन, हेटमायर और होप को लेकर वे इतने आशान्वित हैं क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया की किसी भी टीम में जगह बनाने में सक्षम हैं। जैसन होल्डर की अगुआई में टैस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ समय में वेस्ट इंडीज के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है।

एकदिवसीय क्रिकेट में फिनिशर की शानदार भूमिका निभाने वाले 24 साल के पूरन को अभी टैस्ट में मौका नहीं मिला है जबकि 23 साल के हेटमायर ने 16 टैस्ट खेले हैं। 26 साल के होप इन तीनों में सबसे अनुभवी हैं जिन्होंने 31 टैस्ट में दो शतक लगाए हैं।

एटीपी प्रमुख को अगस्त में वापसी की उम्मीद, लेकिन सत्र खत्म होने का भी डर

मिलान, 10 अप्रैल (एएफपी)।

विश्व पुरुष टेनिस की सर्वोच्च संस्था एटीपी के प्रमुख आंद्रिया गौंडेंजी ने कहा कि उन्हें अब भी टेनिस सत्र के अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है लेकिन उन्होंने साथ ही आगाह भी किया कि कोरोना विषाणु के कारण हो सकता है कि इस साल आगे खेल ही न हो पाए।

गौंडेजी ने कहा, कोई नहीं जानता कि हम कब पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में खेल पाएंगे। अगस्त, सितंबर, नवंबर की बातें करना अभी काल्पनिक है। जिस चीज के अभी होने की संभावना नहीं दिख रही है हम उसके लिए सिर नहीं पटक सकते। यह भी हो सकता है कि हमें अगले साल शुरुआत करनी पड़े। लंदन में अपने आवास से इतालवी मीडिया के साथ बातचीत में गौंडेजी ने कहा कि वह अगस्त में टेनिस सत्र की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इस साल जनवरी में एटीपी अध्यक्ष का पद संभालने वाले 43 वर्षीय गौंडेजी ने कहा, हमने टूर्नामेंटों के अपने कैलेंडर के 50 संस्करण तैयार किए हैं जिनमें हम हर दिन बदलाव करते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अगस्त में शुरुआत करने में सफल रहते हैं तो हम तीन ग्रैंडस्लैम और छह मास्टर्स 1000 को बचा देंगे। ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। पिछले महीने के शुरू से ही टेनिस टूर्नामेंट बंद पड़े हैं और विंबलडन के दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द होने से उसके 13 जुलाई से

कहा कोई नहीं जानता कि हम कब पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में खेल पाएंगे

पहले वापसी की संभावना भी नहीं है। फ्रेंच ओपन भी सितंबर-अक्तूबर तक स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट मई-जून में होना था। गौडेंजी ने कहा, यह एक बड़ी चिंता है। कई सवाल है कि हम फिर से कब खेलेंगे। इसका कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि हम कब वापसी कर पाएंगे। एक बात निश्चित है कि अभी हमने स्वास्थ्य और सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चुना है। उन्होंने कहा, हमने तब इंडियन वेल्स को रद्द कर दिया था जबकि एनबीए चल रहा था। यह जोखिम भरा होता क्योंकि इंडियन वेल्स में अधिकतर खिलाड़ी वहां पहुंच चुके थे और खेलने के इच्छुक थे। हमने बंद स्टेडियमों में खेलने पर भी विचार किया लेकिन फिर तत्काल ही नहीं खेलने का फैसला कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि फ्रेंच ओपन के आयोजकों पर विचार विमर्श किए बिना टूर्नामेंट स्थगित करने के फैसले के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौंडेजी ने कहा, अभी हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं।

इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू शृंखला में देर होने की आशंका जताई

लंदन 10 अप्रैल (भाषा)।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख एशले जाइल्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जून में प्रस्तावित घरेलू शृंखला के आयोजन में देरी होने आशंका जताते हुए कहा कि तीन मैचों की यह शृंखला कोरोना के संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगी।

इंग्लैंड में चार दिवसीय मुकाबले वाली काउंटी चैंपियनशिप रविवार को शुरू होने वाली थी लेकिन यहां किसी भी तरह की क्रिकेट प्रतियोगिता को 28 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस स्थगन के आगे बढ़ने की आशंका है। इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ चार जून से शुरू होने वाली तीन मैचों की टैस्ट शृंखला में भाग लेना है जिसका पहला मुकाबला ओवल में खेला जाना है। इंग्लैंड टीम के निदेशक जाइल्स ने गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में संवाददाताओं से कहा, हमारे लिए अभी भी 28 मई की समय सीमा है लेकिन मुझे लगता है इस बात की संभावना काफी कम है कि हम जून में कोई क्रिकेट खेल पाये।

पोषण संबंधी पाठ्यक्रम पूरा कर रहे घोषाल

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा)।

शीर्ष स्क्वाश खिलाड़ी सौरव घोषाल पूर्ण बंदी के समय का इस्तेमाल पोषण संबंधी प्रमाणित पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कर रहे हैं।

स्क्वाश में पूर्ण फिटनेस की जरूरत होती है और घोषाल काफी फिट हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर फिट रहने के लिए खान-पान काफी अहम होता है और वह इस अनिश्चित ब्रेक का इस्तेमाल भोजन विज्ञान के बारे में जानकारी लेने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पूरे समय घर पर ही हो तो, आपके लिए नई चीजें सीखना काफी अहम है।

शतरंज खिलाड़ियों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिया अपना योगदान **सहायता** 'आओ मिलकर कोरोना से लड़ें' मुकाबले में जुटाई धनराशि

'प्रधानमंत्री राहत कोष' के लिए जमा किए 2.39 लाख रुपए

चेन्नई, 10 अप्रैल (भाषा)।

देश के 17 ग्रैंडमास्टर और 180 से अधिक शतरंज खिलाड़ियों ने आनलाइन ब्लिट्ज प्रतियोगिता में भाग लेकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 'प्रधानमंत्री राहत कोष' के लिए 2.39 लाख रुपए जमा किया।

यहां जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 'चेसबेस इंडिया' नामक शतरंज पोर्टल द्वारा गुरुवार को आयोजित 'लेट्स फाइट कोरोना टूगेदर (आओ मिलकर कोरोना से लड़ें) मुकाबले में भारत के नंबर दो खिलाड़ी विदित गुजराती, राष्ट्रीय चैंपियन अरविंद चिदंबरम और निहाल सरीन ने भी भाग लिया। गुजराती, सरीन और चिदंबरम

नौ दौर के बाद एक समान आठ अंक के साथ शीर्ष पर रहे लेकिन टाईब्रेक में सरीन विजेता बने।

इस मुकाबले का मुख्य मकसद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 'पीएम केयर्स' के लिए कोष इकट्ठा करना था जिससे कुल 2,39,742 रुपए जमा किए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी बंद है। गुजरती ने अपने खेल का दो घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग कर 37,028 रुपए जुटाए। गुजराती, सरीन और चिदंबरम के अलावा युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और अनुभवी दिव्एंदु बरुआ ने भी इसमें भाग लिया। ग्रैंडमास्टर अर्जुन इरिगासी ने 25,000 जबकि ग्रैंडमास्टर शशिकरण, नीलोत्पल दास और बरुआ ने 20-20 हजार रुपए दान दिए। इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों को कम से कम 100 रुपए का दान करना था।

तेंदुलकर ने अब महीने में 5000 लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पहले ही 50 लाख रुपए का दान दे चुके महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अब एक महीने में 5000 लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया है। एक गैर सरकारी संगठन अपनालय ने ट्वीट के जरिए तेंदुलकर को धन्यवाद दिया। अपनालय ने अपने अधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया, शुक्रिया सचिन तेंदुलकर अपनालय की मदद करने के लिए। अपनालय इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी से गुजर रहे लोगों की मदद करता है। वह एक महीने में करीब 5000 लोगों के राशन की जिम्मेदारी लेंगे। तेंदुलकर ने जवाब दिया, अपनालय को शुभकामनाएं और जरूरतमंदों के लिए अपना काम जारी रखिए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 145 *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com